



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2018/चैत्र 29, 1940

No. 139]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2018/CHAITRA 29, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2018

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण., इंडोनेशिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं.-7/8/2017 - डी जी ए डी.—समय समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम 1975 (इसके पश्चात भी अधिनियम के रूप में संदर्भित) और समय समय पर यथा संशोधित उसका सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात भी नियमावली के रूप में संदर्भित); निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) ने चीन जन. गण., इंडोनेशिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (इसके पश्चात संबद्ध देशों के रूप में संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड" (इसके पश्चात संदर्भ वस्तुओं के रूप में संदर्भित) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। प्राधिकारी ने दिनांक 19 मार्च, 2012 के अपने प्रारंभिक जांच परिणाम संख्या 14/45/2010-डी जी ए डी के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 7 जून, 2012 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 32/2012-सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से शुल्क लगाये गए थे। प्राधिकारी की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 2013 के अधिसूचना संख्या 14/45/2010 - डी जी ए डी के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। इन जांच परिणामों के आधार पर, संबद्ध देशों से आयात किए गए संबद्ध वस्तुओं निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2013 के अधिसूचना संख्या 6/2013 - सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से लगाये गये थे।

- जबकि, सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क (5) के संबंध में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को यदि पूर्व में रद्द न किया गया हो, तो यह इस प्रकार से पाटनरोधी शुल्क लगाने की तिथि से 5 वर्षों के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा।

2. और, उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात की जांच करने के लिए इस कदम के समाप्त होने की तिथि से पूर्व उचित समयावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत स्थापित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करेगा कि क्या शुल्क के समाप्त होने से संभवतः पाटन और क्षति जारी रहेगी अथवा फिर से होगी।
3. जबकि, इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार मैसर्स सेंट गोविन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके पश्चात 'याचिकाकर्ता' के रूप में संदर्भित) द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें चीन जन. गण., इंडोनेशिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का आरोप लगाते हुए पांच वर्षों की आगे की अवधि के लिए इन शुल्कों को बढ़ाने के लिए 'प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड' के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा आरंभ करने का अनुरोध किया गया है।
4. और जबकि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिनांक 5 जून, 2017 को एक अधिसूचना संख्या 7/8/2017 – डी जी ए डी जारी की है, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है जिसके माध्यम से इस बात की जांच करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के अनुसार संबद्ध जांचों को शुरू किया गया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए उपर्युक्त वस्तुओं के आयात पर उक्त शुल्कों की समाप्ति से संभवतः घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होगी।
5. वर्तमान समीक्षा के कार्यक्षेत्र में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए उपर्युक्त वस्तुओं के आयातों के संबद्ध में मूल जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

प्रक्रिया

6. यहां नीचे उल्लेख की गई प्रक्रिया का पालन प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में की गई है:
 - i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए कार्यवाही करने के पूर्व पाटनरोधी आवेदन की निर्णायक समीक्षा के प्राप्त होने के बारे में भारत में चीन जन. गण., इंडोनेशिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास को अधिसूचित किया है।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 5 जून, 2017 की आम सूचना जारी की।
 - iii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास को और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को इस आवेदन का अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
 - iv. भारत में संबद्ध देशों के दूतावास से भी यह अनुरोध किया गया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें। इन उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति इन देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ साथ उन्हें भेजी गयी थी।
 - v. प्राधिकारी ने भारत में चीन जन. गण., इंडोनेशिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास को, उपलब्ध कराये गए पते के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।
 - vi. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनका ब्यौरा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए अवसर प्रदान किया।
 1. जिप्सेम्ना कंपनी (एल. एल. सी.), संयुक्त अरब अमीरात
 2. द सियाम जिप्सम इंडस्ट्री (साराबुरी), कं. लिमि., थाईलैंड
 3. पीटी. सियाम इंडो जिप्सम इंडस्ट्री, इण्डोनेशिया
 4. पीटी. पेट्रोजया बोरल प्लास्टरबोर्ड, इण्डोनेशिया
 5. शॉन बेयर बिल्डिंग मेटेरियल, चीन
 6. लिनी हुआमेई जिप्सम बिल्डिंग, चीन
 7. सियनमीनरेशनल कारपोरेशन, चीन

- vii. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उपर्युक्त मामले में प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं।
1. मैसर्स जिप्सेमना कंपनी (एल. एल. सी.), संयुक्त अरब अमीरात
 2. मैसर्स सियाम जिप्सम इंडस्ट्री (सोंगखला) कं. लिमि.
 3. मैसर्स सियाम जिप्सम इंडस्ट्री (साराबुरी), कं. लिमि.
 4. मैसर्स पीटी. पेट्रोजया बोरल प्लास्टरबोर्ड
 5. मै. पीटी. सियाम- इंडो जिप्सम इंडस्ट्री
- viii. जांच प्रारंभ करने के बाद, एक अन्य कम्पनी नामतः नौफ एल एल सी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ने प्राधिकारी को केवल एक पत्र प्रस्तुत किया था परंतु निर्यातक के प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ix. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संघों (जिनके नाम व पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गए थे) को जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भी अग्रेषित की और उन्हें नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने की सलाह दी:
1. मैसर्स सस्था सीनियर बिल्डिंग प्रॉडक्ट
 2. मैसर्स लाफारजे बोरल जिप्सम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
 3. मैसर्स लाफारेजे बोरल जिप्सम इण्डिया प्राइवेट
 4. मैसर्स विकास ट्रेडिंग कम्पनी
 5. मैसर्स टोटल सॉल्यूशन बिल्डिंग मेटेरियल कं.
- x. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी आयातक ने प्राधिकारी द्वारा भेजी गयी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- xi. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- xii. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन देन वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा गणना के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है और इन लेन देन की उचित जांच की पश्चात विश्लेषण को आवश्यक बताया है।
- xiii. जांच की अवधि जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 (12 महीने) है और क्षति के निर्धारण के उद्देश्य से, अवधि अर्थात् अप्रैल, 2013 से मार्च 2014, अप्रैल 2014 से मार्च 2015, अप्रैल 2015 से मार्च 2016 और जांच की अवधि पर विचार किया जाएगा।
- xiv. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जिस सीमा तक इसे आवश्यक समझा गया। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक इस जांच के उद्देश्य से उसे आवश्यक समझा गया।
- xv. सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांत (जी ए ए पी) के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और उसकी बिक्री करने के उत्पादन और लागत का आदर्शात्मक लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एन आई पी) इस प्रकार से तय किया गया है जिससे यह पता चल सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में अपेक्षाकृत कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvi. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 6 मार्च, 2018 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की जिसमें घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने अनुरोध को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध को संकलित करें और उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे उसके पश्चात अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

- xvii. निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है, को गैर सहयोगी हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया है।
- xviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक हुआ, इस प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना पर गोपनीय के रूप में विचार किया गया है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।
- xix. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना देने प्राप्त कराने से इन्कार किया है अथवा अन्य प्रकार से इसे उपलब्ध नहीं कराया है अथवा पर्याप्त रूप से जांच में अवरोध उत्पन्न किया है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को गैर सहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस जांच परिणाम को रिकार्ड किया है।
- xx. ऊपर में दी गई नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा संबंधित हितबद्ध पक्षकारों आवश्यक तथ्यों के बारे में बताया गया था। प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- xxi. इस दस्तावेज में “***” इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए अनुसार और गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना द्योतक है।
- xxii. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 67.96 रुपये है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

7. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है:
- वर्तमान जांच की एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र को उस से नहीं बदला जा सकता है जो मूल जांच में था।
 - हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से मौजूदा बहिर्ग के अलावा अगली पीढ़ी के मानक बोर्ड (अगली पीढ़ी) को भी बाहर किया जाना होगा क्योंकि यह एक उत्पाद है जिसका निर्माण अथवा आयात भारत में जांच की अवधि के दौरान नहीं किया गया है। भारत में आयात अथवा निर्माण नहीं किए जाने की स्थिति में किसी प्रकार का पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि मूल जांच में इसका बहिर्ग उनकी भौतिक/ तकनीकी विनिर्देशनों, उपयोग, प्रतिस्थापनियता आदि के आधार पर कुछ उत्पादों को प्रदान किए गए थे। पहले से उपलब्ध बहिर्ग के अलावा किसी बहिर्गमन को इसी मानदण्ड से होकर गुजरना होता है। हालांकि, यदि प्राधिकारी का जांच के पश्चात यह मत हो कि इसकी भौतिक/ तकनीकी विनिर्देशनों, उपयोगिता, प्रतिस्थापनीयता आदि के आधार पर किसी विशिष्ट उत्पाद को बाहर निकाला जाना चाहिए तब घरेलू उद्योग के पास इसके विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं होती है।

उत्पादकों/ निर्यातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है:
- विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से मौजूदा बहिर्गमन के अलावा अगली पीढ़ी के मानक बोर्ड (अगली पीढ़ी) को भी बाहर किया जाना होगा क्योंकि यह एक उत्पाद है जिसका निर्माण अथवा आयात भारत में जांच की अवधि के दौरान नहीं किया गया है। भारत में आयात अथवा निर्माण नहीं किए जाने की स्थिति में किसी प्रकार का पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद सभी मोटाई और आकार के जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है, “प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड” है :
- वह जिप्सम बोर्ड जिसमें 5 प्रतिशत तक और उसको शामिल करते हुए जल अवशोषण हो (नमी प्रतिरोधक बोर्ड)।
 - जिप्सम बोर्ड जिसमें प्रति मिलीमीटर की मोटाई वाला देशांतर दिशा में 50 न्यूट्रॉन और विपर्य में 24 न्यूट्रॉन का न्यूनतम ब्रेकिंग भार को (प्रभाव प्रतिरोधी बोर्ड अथवा अग्नि प्रतिरोधी बोर्ड)।

- ग. अग्नि बोर्ड
घ. अग्नि ताप बोर्ड
ङ. नमी अवरोधक के साथ जिप्सम सीलिंग बोर्ड
च. इको बोर्ड
छ. ताप बोर्ड
ज. मॉडल विरोधी बोर्ड अथवा मौसम बोर्ड
झ. तापीय बोर्ड
ञ. श्वेत फिल्म में सील किया हुआ अल्युमिनियम किनारे वाले जिप्सम सीलिंग बोर्ड
10. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण अध्याय शीर्ष 68091100 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि, संबद्ध वस्तुओं का भी आयात शुल्क शीर्ष 68091900 के अंतर्गत किया जा रहा है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। चूंकि वर्तमान जांच लागू शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है। अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जिसकी परिभाषा मूल जांच में दी गई है।
11. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-
“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
12. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए उत्पाद में कोई अधिक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद की तुलना भौतिक लक्षणों उत्पादन प्रौद्योगिकी और निर्माण प्रक्रिया, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन के मामले में आयात किए गए संबद्ध उत्पाद से की जा सकती है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन के योग्य हैं।
13. प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्माण किया गया उत्पाद और संबद्ध देश से भारत में आयात किये गये संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अभिप्राय के अनुसार समान वस्तु है।

घरेलू उद्योग का कार्य क्षेत्र एवं स्थान

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

14. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- निर्णायक समीक्षा के लिए अनुरोध मैसर्स सेंट-गोबिन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक उन घरेलू उत्पादन का लगभग 84 प्रतिशत होता है जिस पर विचार संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का एक बड़े भाग के रूप में किया जा सकता है।
 - याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा आयातक से (या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से) संबंधित नहीं है। इस प्रकार से याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2ख और 5(3) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है।
 - हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि घरेलू उद्योग का संबद्ध देशों में संबंधित पक्षकार है अतः पाटनरोधी नियमावली के मामले में एक घरेलू उद्योग के रूप में इसे नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि इसका संबद्ध देश में से किसी देश में कोई संबंधित पक्षकार नहीं है जो भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों अथवा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगा हुआ है। उसके संबंध में एक घोषणा पहले ही याचिकाकर्ता के पास दायर है। घरेलू उद्योग का आगे यह अनुरोध है कि हितबद्ध पक्षकार गलत तर्कों एवं तुच्छ आरोपों को लगाकर इस जांच के ठोस पहलुओं से प्राधिकारी का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है।
 - हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क लिया है कि घरेलू उद्योग ने इस तथ्य को छुपाया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का दो से अधिक उत्पादक हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि दो उत्पादकों, विशेष रूप से घरेलू उद्योग द्वारा जिसका इस याचिका में उल्लेख किया गया है, के अलावा भारत में संबद्ध वस्तुओं का कुछ अन्य उत्पादक है। इस संबंध में घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि वास्तव में बहुत कम विनिर्माता हैं जो भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षमताओं को खपाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, घरेलू उद्योग की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उनमें से कुछ जांच की अवधि के पूर्व जांच के

अधीन थे अथवा बहुत कम मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। इन उत्पादकों के लघु अथवा बहुत मामूली प्रचालन के कारण, घरेलू उद्योग जांच प्रारंभ करने के समय इन उत्पादकों के संबंध में सूचना और आंकड़े प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे। किसी भी मामले में इन नए बाजार भागीदारों का उद्भव अपने आप में यह सिद्ध करता है कि संबद्ध देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क प्रभावी हुआ है। हालांकि, संबद्ध देशों से इन निर्यातकों के पास बहुत अधिक क्षमताओं के कारण निर्यात बाजार में इन वस्तुओं को पाटित करने के लिए उनके निर्यात उन्मुखीकरण और उनकी प्रवृत्ति, यदि शुल्कों समाप्त किए जाने की अनुमति दी जाती है तब यह घरेलू उद्योग और नए उभर रहे निर्माताओं के लिए बहुत अधिक हानिकारक होगा।

उत्पादकों/ निर्यातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

15. घरेलू उद्योग के स्थान के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

- i. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग प्राधिकारी के समक्ष निष्पक्ष रूप में नहीं आया है और इसने तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने के संबंध में जांच प्रारंभन प्राप्त किया है। यह उल्लेख किया जाता है कि भारत में समान वस्तु के केवल 2 उत्पादक हैं जबकि ऐसे कई अन्य उत्पादक हैं जिनके पास पर्याप्त क्षमताएं हैं।
- ii. आवेदक का संयुक्त अरब अमीरात, इण्डोनेशिया और थाईलैंड नामतः सेंट गोबिन ग्रायप्रॉक संयुक्त अरब अमीरात, सेंट गोबिन इण्डोनेशिया और ग्रायप्रॉक (सेंट गोबिन) थाईलैंड में संबंधित पक्षकार हैं। आवेदक इन देशों में अपने निजी उत्पादन होने के साथ साथ संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहता है। इस प्रकार से आवेदक दोनों विश्व में सर्वोत्तम की इच्छा रखते हैं। जबकि, इन देशों उत्पादकों को हानि हो सकती है। इसके अलावा, आवेदक ने उन उत्पादों को बाहर कर दिया है जिसका उत्पादन इसके संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्देशों में किया जाता है ताकि याचिकाकर्ता इन देशों से इसका आयात कर सकें। यह केवल पात्रता तक सीमित प्रश्न नहीं है बल्कि याचिकाकर्ता से अन्य प्रकार से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह याचिकाकर्ता के आचरण तक है, इसकी चयनित रूप में आपूर्ति स्रोतों को प्रतिबंधित करने की मंशा है और साथ ही साथ वैश्विक उत्पादन के लाभ को भी प्राप्त करना है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

17. वर्तमान मामले में मैसर्स सेंट गोबिन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा याचिका दायर की गई है। जांच की अवधि के दौरान भारतीय उत्पादकों का उत्पादन और हिस्सा नीचे दिया गया है:

विवरण	जनवरी 16- दिसंबर 16 (जांच की अवधि)	
	एम3	हिस्सा
मैसर्स सेंट गोबिन इण्डिया प्रा. लिमि.	***	84%
मैसर्स यू एस जी बारल बिल्डिंग प्रॉडक्ट्स (इण्डिया) प्रा. लिमि.	***	16%
कुल	***	100%

18. उपर्युक्त से यह उल्लेख किया जा सकता है कि कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 84 प्रतिशत आवेदक का हिस्सा होता है जिस पर संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के एक बड़े भाग के रूप में विचार किया जा सकता है।
19. केवल याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का लगभग 84 प्रतिशत होता है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता ने नियम 5(3) के अंतर्गत स्थान की आवश्यकता को पूरा कर लिया है और यह नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग होता है।
20. हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के संबंध में की याचिकाकर्ता संबद्ध देशों में से कुछ देशों में संबंधित पक्षकार है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि इसका संबद्ध देशों में से किसी देश में कोई संबंधित पक्षकार नहीं है जो संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन अथवा व्यापार में लगा हुआ है।

21. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लेख किए गए दो उत्पादकों के अलावा, जांच की अवधि के दौरान अन्य भारतीय उत्पादक थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि नए रूप से उभरते हुए उत्पादकों के बहुत आरंभिक प्रचालन के कारण वे जांच प्रारंभ किए जाने के समय इन उत्पादकों के संबंध में सूचना प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे। किसी के मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक का पर्याप्त हिस्सा है जिसे पाटनरोधी नियमावली के संबंध में एक घरेलू उद्योग के रूप में माना जा सकता है। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है, नए भारतीय उत्पादकों का उद्भव एक स्पष्ट प्रमाण है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लागू रहे।

गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

22. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है:
- याचिकाकर्ता केवल इस प्रकार की सूचना को गोपनीय के रूप में दावा किया है जिसकी गोपनीयता की अनुमति नियमों के अंतर्गत और प्राधिकारी के सतत् प्रथा के अनुसार दी गई है।
 - याचिकाकर्ता आवेदन के पर्याप्त गैर गोपनीय पाठ को उपलब्ध कराया है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार सूचना का किसी विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख करने में सक्षम नहीं है जिसका दावा गोपनीय के रूप में किया गया है और जिसकी गोपनीयता का औचित्य इस नियमावली के अंतर्गत बताया गया हो।
 - भारत में निर्यात की मात्रा, घरेलू बाजार में बिक्री की समग्र मात्रा, उत्पादन, बिक्री, भारत में निर्यात के लिए औसत कीमत बेशी सूचना सूचीबद्ध पाठ में प्रदान की गई है क्योंकि यह सूचना व्यापार स्वामित्व संबंधी सूचना है।
 - किसी भी निर्यातक ने गैर गोपनीय पाठ उपलब्ध नहीं कराया है जो उनके गोपनीय पाठ की एक प्रतिलिपि है। उन्होंने मात्रा से संबंधित सभी सूचनाओं को गोपनीय रखा है। उन्होंने गोपनीयता के दावों के संबंध में कोई विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा, ये उत्तर निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर का गैर गोपनीय पाठ दायर करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी विशिष्ट दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। इस कारण से हम माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर ध्यान न दें और इसके साथ ही निर्यातकों के उत्तर को अस्वीकार कर दें और उन्हें अलग अलग दर्जा देने से इन्कार करें।

उत्पादकों/ निर्यातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

23. गोपनीयता के संबंध में वर्तमान जांच की अवधि के दौरान उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत मानी गयी सीमा नीचे दिए गए अनुसार है:
- इस याचिका में अत्यधिक गोपनीयता का इस्तेमाल किया गया है। यह याचिका मात्रा के संबंधित सूचना के संबंध में पूर्ण रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है।
 - घरेलू उद्योग ने दावा किया है और इसे अर्थ में अत्यधिक गोपनीयता की अनुमति दी गई है कि उन्होंने सार्वजनिक फाईल में अपनी वार्षिक रिपोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया है।
 - घरेलू उद्योग ने भी अपनी लागत का पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक याचिका के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“गोपनीय सूचना”

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

26. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता की पर्याप्तता के दावे के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसे प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक याचिका के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य

27. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा।
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

28. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध निम्नानुसार है :-

- i. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में पूरी सूचना प्रस्तुत की थी जो किसी जांच के प्रारंभ करने के उद्देश्य से आवश्यक था। नियम 5 के संबंध में, घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित है कि वह सूचना दे जो किसी जांच को प्रारंभ करने के औचित्य को ठहराने के लिए पर्याप्त हो। आवश्यक साक्ष्य भी सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के उनके दावे के समर्थन में उपलब्ध कराया गया था।
- ii. चीन को प्राधिकारी द्वारा पूर्व मामलों में ली गई स्थिति के अनुरूप तथा अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए। चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के दृष्टिकोण

29. चीन जन. गण. के लिए आवेदन में परिकलित सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 (7) के अंतर्गत यथा प्रावधान की गई आवश्यकताओं का उल्लंघन है। जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना के पैरा 10 तथा आवेदन में यह शर्त रखी गई है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य की गणना विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

30. जांच प्रारंभ करने के चरण में, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश के रूप में मानकर इस पूर्वानुमान के साथ कार्यवाही शुरू की थी। जांच आरंभ करने पर प्राधिकारी ने चीन में इन उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दी थी कि वे जांच प्रारंभ करने की सूचना का उत्तर दें और बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का निर्धारण करने के लिए संगत सूचना

उपलब्ध कराये। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान का खण्डन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों एम ई टी प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन की सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वे अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दें। हालांकि, चीन के किसी भी उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यातक प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है।

31. तदनुसार, संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिए अनुसार किया गया है :

चीन जन. गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

32. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से अनुबंध 1 के पैरा 7 के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। चीन जन. गण. से भारत में आयात किए गए संबद्ध उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रमुख कच्चे मालों के लिए घरेलू उद्योग के आदर्शतम खपत मानदण्डों पर विचार करते हुए किया गया है, कच्चे माल की लागत घरेलू उद्योग के लिए अनुमति दिए गए स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, परिवर्तन लागत, ब्याज, एस जी ए आदि के अनुसार है। ब्याज को छोड़कर बिक्री के लागत का 5 प्रतिशत की अनुमति उचित लाभ के लिए दी गई है।

चीन जन. गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

33. चीन जन. गण. के किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत का ब्यौरा देते हुए किसी सूचना को उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण से प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के लेन देन वार आंकड़ों के आधार पर बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, चीन जन. गण. के सभी निर्यातकों के संबंध में कारखानागत स्तर पर भारित औसत निवल निर्यात कीमत का निर्धारण पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह संबंधी खर्च, बैंक प्रभार, कमीशन और अंतर्देशीय भाड़े के लिए उचित समायोजन करने के बाद किया गया है।

मैसर्स जिप्समना कंपनी (एल. एल. सी.), दुबई तथा संयुक्त अरब अमीरात में अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत का निर्धारण

34. मैसर्स जिप्समना कंपनी (एल एल सी), दुबई : निर्यातक द्वारा दायर किये गये प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई है। वह पूर्ण है और सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उत्पादन की लागत का निर्धारण उत्पादक के सत्यापित सूचना के आधार पर किया गया था और घरेलू बिक्री और लेन देन की जांच की गई थी और यह पाया गया कि घरेलू बिक्री व्यापार की सामान्य अवधि में हुई है। इस कारण से प्राधिकारी ने पूर्ण घरेलू बिक्री के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्यवाही की है। उत्पादक ने दुलाई, ऋण की लागत, बीमा के कारण समायोजन का दावा किया है और उसे आवश्यक सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। सामान्य मूल्य को नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।
35. संयुक्त अरब अमीरात में अन्य उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का सह-संबंध मैसर्स जिप्समना कंपनी के लिए तय किए गए सामान्य मूल्य के साथ स्थापित किया गया है।
36. मैसर्स जिप्समना कंपनी (एल एल सी), दुबई के लिए निर्यात कीमत : जांच की अवधि के दौरान मैसर्स जिप्समना कंपनी (एल एल सी), दुबई ने भारत में संबद्ध वस्तुओं का प्रत्यक्ष तौर पर निर्यात किया है। निर्यातक ने कमीशन, अंतर्देशीय दुलाई, विदेश में दुलाई, बैंक प्रभार, ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया है और उसे आवश्यक सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। निर्धारित निवल निर्यात कीमत को नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।
37. प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के लेन देन वार आंकड़ों के सह-संबंधित रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार उत्तर न देने वाले अन्य निर्यातकों के लिए निर्यात की कीमत का निर्धारण किया है।

इंडोनेशिया और थाईलैंड से उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान इंडोनेशिया और थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं किया गया था। यह भी नोट किया जाता है कि निम्नलिखित निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और उसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार लिया गया है :

- क. मैसर्स सियाम जिप्सम इण्डस्ट्री (सोंगखला) कं. लिमि.
- ख. मैसर्स सियाम जिप्सम इण्डस्ट्री (सराबूरी) कं. लिमि.
- ग. मैसर्स पी टी पेट्रो जया बोरल प्लास्टरबोर्ड
- घ. मैसर्स पी टी सियाम-इण्डो जिप्सम इंडस्ट्री

पाटन मार्जिन

39. संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण तय किए गए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत से तुलना कर किया गया है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देशों से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए परिकल्पित पाटन मार्जिन का दर्शाता है।

क्र. सं.	देश	उत्पादक / निर्यातक	सामान्य मूल्य (यू एस डॉलर / एम3)	शुद्ध निर्यात मूल्य (यू एस डॉलर / एम3)	पाटन मार्जिन (यू एस डॉलर / एम3)	पाटन मार्जिन %	रेंज %
1	चीन	सभी उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	100-110
2	संयुक्त अरब अमीरात	मैसर्स जिप्समना कं. (एल. एल. सी.), दुबई	***	***	***	***	10-20
		अन्य कोई उत्पादक	***	***	***	***	55-65

क्षति के आकलन और क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच के लिए पद्धति**घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

40. घरेलू उद्योग द्वारा वर्तमान जांच की अवधि के दौरान किए गए क्षति संबंधित अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :
- विचाराधीन उत्पाद के आयातों में जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि के साथ इन वर्षों में अधिक वृद्धि दर्शायी है। आयातों ने भी भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि दर्शायी है।
 - लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, मांग में संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हो रही है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कमी आई है। ऐसा संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुआ है।
 - विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमतों में कटौती के साथ, भारतीय उत्पादक के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प अपनी कीमतों को आयात कीमतों में परिवर्तन के साथ उसके अनुकूल बनाना है अथवा ऑर्डर को खोना है और इस कारण से बाजार हिस्से को भी खोना है।
 - घरेलू उद्योग की कीमतें उन कीमतों के प्रभाव को दर्शाती हैं जिनकी पेशकश आयातकों द्वारा घरेलू बाजार में की जा रही है।
 - कम कीमत पर बिक्री, कीमत में कटौती सकारात्मक और वास्तविक है। इसके अलावा घरेलू उद्योग को कीमत पर दबाव के कारण हानि हो रही है क्योंकि वे अपनी कीमतों उचित स्तर तक बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। इसके लिए मुख्य कारण चीन से आयातों की अधिक मात्रा और वह भी पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर है।
 - घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के मामले में बहुत अधिक सीमा तक तेजी से गिरावट आई है।
 - घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट चीन से गैर लाभप्रद कीमतों आयात की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि के कारण हुई थी।
 - बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि की तुलना में कम थी और इस प्रकार से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव का प्रभाव बन रहा है।
 - घरेलू उद्योग को चीन से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के संबंध में वास्तविक क्षति हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को उस स्थिति में लगातार क्षति होने का खतरा है यदि वर्तमान स्थिति जारी रहे।

उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

41. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वर्तमान जांच की अवधि के दौरान किए गए क्षति संबंधित अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :
- घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है और क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान इसमें सुधार हुआ है।

- ii. इण्डोनेशिया और थाईलैंड से कोई आयात नहीं हुआ है। इस कारण से इन दो देशों से आयातों के कारण किसी क्षति के होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- iii. कीमत में कोई कटौती, कीमत दबाव और कीमत में ह्रास नहीं हुआ है और इस कारण से संबद्ध देशों से आयातों के कारण होने वाली किसी क्षति का घरेलू उद्योग के दावे को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- iv. घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्से, लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय आदि के मामले में बहुत अधिक सुधार हुआ है। इस कारण से यह सिद्ध किया गया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- v. घरेलू उद्योग क्षति और पाटन के जारी रहने अथवा इसके फिर से होने की किसी संभावना को सिद्ध करने में असफल हो गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

42. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।
43. क्षति के न होने के अनुरोधों के संबंध में, यहां नीचे तय की गई क्षति विश्लेषण इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए सतह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग पाटन से क्षति हुई है।
44. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में जांच की अवधि के दौरान किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोधों की नीचे दिए गए अनुसार जांच की गई है और उसका समाधान किया गया है :
45. पाटनरोधी नियमावली में अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह मात्रा और कीमत दोनों के प्रभाव की जांच करने के बाद क्षति की जांच करे। क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों का कीमतों पर प्रभाव और (ख) इन आयातों का घरेलू उद्योगों पर परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल है। पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस पर विचार करे कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष अथवा स्वतंत्र रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इन कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस तथ्य पर विचार करे कि क्या भारत में तमाम उत्पाद की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक कीमतों पर दबाव पड़ता अथवा कीमत वृद्धि रुक जाती जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक हुआ होता।
46. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है :

(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।

47. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदण्ड गिरावट को दर्शाते हों। कुछ मानदण्ड गिरावट को दर्शा सकते हैं जबकि कुछ में सुधार भी देखा जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी सभी क्षति मानदण्डों पर विचार करते हैं और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं प्राधिकारी ने इन अनुरोधों में तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखकर वस्तुपरक तरीके से क्षति मानदण्डों की जांच की है।

संचयी आकलन

48. संचयी आकलन के संबंध में नियमावली के अनुबंध II (iii) में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

उन मामलों में जहां एक से अधिक देश से किसी उत्पाद का आयात पाटनरोधी जांच के एक ही समय में अध्याधीन हो रहा हो, तब निर्दिष्ट प्राधिकारी इस प्रकार के आयातों के प्रभावों का तभी संचयी रूप से आकलन करेंगे जब यह निर्धारित करता हो कि (क) प्रत्येक देश से आयात की तुलना में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत है अथवा जहां अलग अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, ये आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक होता है और (ख) आयात के प्रभाव का संचयी आकलन आयात की गई वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतियोगिता की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयात भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से एक ही साथ हो रहे हैं। इस कारण से इन स्रोतों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संचयी आकलन के मुद्दे की जांच इस नियमावली के अनुबंध ॥ (iii) मानदण्डों के संबंध में की गई है। इसमें यह देखा गया था कि :

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जनवरी - 16 दिसंबर - 16
आयात					
चीन गणराज्य	एम3	367	5	287	1,014
थाईलैंड	एम3	586	123	0	0
संयुक्त अरब अमीरात	एम3	12,412	18,247	45,177	63,509
इंडोनेशिया	एम3	0	0	0	0
कुल संबंधित देश	एम3	13,365	18,375	45,464	64,524
अन्य	एम3	125,387	164,062	204,499	216,712
कुल आयात	एम3	138,752	182,436	249,963	281,235

50. यह तालिका दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान थाईलैंड और इण्डोनेशिया से कोई आयात नहीं हुआ है। इसके अलावा, इण्डोनेशिया ने क्षति की पूरी अवधि के दौरान किसी संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है।
51. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संचयी आकलन के उद्देश्य से, संबद्ध देशों से उत्पादकों से पाटित न किए गए आयातों को क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से लिया गया है।

पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

आयात की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

52. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है कि क्या भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में या तो स्वतंत्र रूप में या इसके सापेक्ष पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
संबंधित देशों से	एम3	13365	18375	45464	64524
अन्य देशों से	एम3	125387	164062	204499	216712
कुल आयात	एम3	138752	182436	249963	281235
घरेलू उद्योग	एम3	446115	487013	554151	599914
अन्य निर्यातक	एम3	98815	105826	107317	111875
भारतीय उत्पादक	एम3	544930	592839	661468	711789
भारतीय खपत	एम3	683682	775275	911431	993024
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देशों से आयात					
कुल उत्पाद	%	2%	2%	5%	7%
कुल आयात	%	10%	10%	18%	23%
कुल खपत	%	2%	2%	5%	7%

53. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है।
54. जैसा कि उपर्युक्त पैरा 50 में दी गई तालिका से देखा जा सकता है, संबद्ध देशों समग्र आयात प्राथमिक रूप से संयुक्त अरब अमीरात और चीन में संकेंद्रित हैं। इस कारण से उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों का हिस्सा प्राथमिक रूप से केवल इन दो देशों से आयातों के प्रभाव को दर्शाता है। इस प्रकार से यह देखा गया है कि इन दो संबद्ध देशों से मात्रा कुल आयातों की तुलना में तथा स्वतंत्र रूप से बहुत अधिक है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

कीमत में कटौती

55. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस पर विचार करे की क्या भारत में तमाम उत्पाद की कीमत से तुलना किए जाने पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा इस प्रकार के आयातों का प्रभाव से अन्य प्रकार से कीमतों पर बहुत अधिक सीमा तक दबाव पड़ता अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक हुई होती।
56. इस संबंध में उत्पाद का पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत जिसमें व्यापार के उसी स्तर पर सभी प्रकार की छूट और कर का निवल शामिल है, के बीच एक तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमत का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया था। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच मूल्य की तुलना की है।

कीमत में कटौती	यू ओ एम	चीन	संयुक्त अरब अमीरात	थाईलैंड	इण्डोनेशिया	संबंधित देश
आयात मात्रा	एम3	1014	63509	0	0	64524
पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुंच मूल्य	रु./ एम3	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	100	0	0	100
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ एम3	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	100	0	0	100
कीमत में कटौती	रु./ एम3	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	35-45	20-30	0	0	20-30
पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	रु./ एम3	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	100			100
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ एम3	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	100			100
कीमत में कटौती	रु./ एम3	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	0-10	0-10	0	0	0-10

57. उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग चीन और संयुक्त अरब अमीरात से क्रमशः 1 प्रतिशत और 6 प्रतिशत कीमत में कटौती हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वे अपनी बिक्री कीमत को संबद्ध देशों से निम्न कीमत पर पाटित आयातों की कीमत दबाव के कारण वृद्धि नहीं कर सके, उपर्युक्त तालिका उसकी पुष्टि नहीं करता है। विशेष रूप से जब घरेलू बिक्री कीमतों में सतत वृद्धि को दर्शाते हुए पैरा 61 में तालिका के साथ जांच की जायेगी/ सह संबंध देखा जायेगा।

कम कीमत पर बिक्री

58. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री के कारण हुई हानि की भी जांच की है। इस उद्देश्य से घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना प्रत्येक देश के आयातों के पहुंच कीमत से की गई है। आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग की क्षति रहित की तुलना नीचे दिए गए अनुसार दर्शाती है :

कम कीमत पर बिक्री	यू ओ एम	चीन	संयुक्त अरब अमीरात	थाईलैंड	इण्डोनेशिया	संबंधित देश
आयात की मात्रा	एम3	1014	63509	0	0	64524
पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुंच मूल्य	रु./ एम3	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	100	0	0	100
क्षति रहित कीमत	रु./ एम3	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	100	0	0	100
कम कीमत पर बिक्री	रु./ एम3	***	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	20-30	0-10	0	0	0-10
पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	रु./ एम3	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	100			100
क्षति रहित कीमत	रु./ एम3	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	100			100
कम कीमत पर बिक्री	रु./ एम3	(***)	(***)	***	***	(***)
कम कीमत पर बिक्री	%	(***)	(***)	***	***	(***)
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	(15) - (5)	(15) - (5)			(15) - (5)

59. उपर्युक्त तालिका से यह यह नोट किया जाता है कि चीन और संयुक्त अरब अमीरात से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक रही है। इसके अलावा, इण्डोनेशिया और थाईलैंड से कम कीमत पर कोई बिक्री नहीं हुई है क्योंकि इन दोनों देशों से कोई आयात नहीं हुआ है।

कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

60. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से की क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में ह्रास अथवा उस पर दबाव बन रहा है और यह कि इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से बहुत अधिक सीमा तक कीमतों पर दबाव पड़ता अथवा कीमत में वृद्धि रूक गई होती जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि की तुलना में लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया है। यह स्थिति नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शायी गई है :

कीमत में ह्रास/ दबाव	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
बिना पाटनरोधी शुल्क के पहुंच मूल्य	रु./ एम3	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	96	98	97
पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	रु./ एम3	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	100	100	100
बिक्री की लागत	रु./ एम3	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	102	92	90
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ एम3	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	103	103	102

61. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य ने पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में ऊपर की ओर की प्रवृत्ति दर्शायी है।

घरेलू उद्योग का आर्थिक मानदण्ड

62. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इस प्रकार उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों, जिनका इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है; उन कारकों जो घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन के आकार पर प्रभाव डालते हों; नकदी के प्रभाव, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश प्राप्त करने पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव डालते हों, का वस्तु परक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।
63. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदण्डों का विश्लेषण यहां नीचे किया गया है।

क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

64. उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे दिए अनुसार था :

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
क्षमता	एम3	605000	645000	663000	699000
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	107	110	116
उत्पादन	एम3	443740	484601	550016	587496
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	109	124	132
क्षमता का उपयोग	%	73%	75%	83%	84%
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	102	113	115

65. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति की पूरी अवधि के दौरान सतत् रूप से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग की भी वही प्रवृत्ति रही जो उत्पादन की प्रवृत्ति रही थी। यह नोट किया जाता है कि संस्थापित क्षमता में भी क्षति की पूरी अवधि के दौरान 16 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

बिक्री मात्रा

66. मात्रा और कीमतों दोनों के मामले में बिक्री मानदण्ड नीचे दर्शाया गया है :

विवरण		2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
घरेलू बिक्री मात्रा	एम3	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	109	124	132
घरेलू बिक्री की कीमत	रु. / एम3	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	103	103	102
कुल बिक्री की मात्रा (निर्यात सहित)	एम3	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	109	124	132
कुल बिक्री की कीमत	रु. / एम3	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	103	103	102

67. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि के साथ क्षति की अवधि के दौरान क्रमिक रूप में वृद्धि हुई है। बिक्री की कीमत भी स्थिर रही है और क्षति की अवधि में क्रमिक रूप से बढ़ती रही है।

बाजार हिस्सा :

68. घरेलू उद्योग के आयातों, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
मांग					
संबद्ध देशों से आयात	एम3	13365	18375	45464	64524
अन्य देशों से आयात	एम3	125387	164062	204499	216712
घरेलू उद्योग बिक्री	एम3	443740	484601	550016	587496
अन्य उत्पादक की बिक्री	एम3	98815	105826	107317	111875
कुल मांग	एम3	681307	772864	907295	980606
मांग में बाजारी हिस्सा					
संबद्ध देशों से आयात	%	2%	2%	5%	7%
अन्य देशों से आयात	%	18%	21%	23%	22%
घरेलू उद्योग बिक्री	%	65%	63%	61%	60%
अन्य उत्पादक की बिक्री	%	15%	14%	12%	11%

69. जैसा की उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात में क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि, भारत में निर्यात करने वाले संबद्ध देशों के ब्यौरे को पैरा 49 में तालिका के साथ मिलान किया जाना है।
70. यह भी नोट किया जाता है कि पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि उसी अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि उस अनुपात में नहीं हुई है। इस कारण से, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट का कारण अन्य देशों के आयातों के कारण हो सकता है जो इस तालिका से स्पष्ट है।

लाभ/हानि, नकदी का प्रभाव, नियोजित पूंजी पर आय

71. घरेलू उद्योग का लाभ / हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

विवरण		2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
लाभ एवं हानि	रु./ एम3	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	146	495	582
लाभ एवं हानि	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	160	607	791
अवमूल्यन	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	112	86	90
नकदी का प्रभाव	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	125	228	280
व्याज और कर पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	160	607	791
नियोजित पूंजी	रु. लाख	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूची	100	81	88	85
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	199	692	930

72. घरेलू उद्योग की समग्र लाभप्रदता मानदण्डों में क्षति की अवधि की तुलना में सुधार हुआ है।
73. यह नोट किया जाता है कि इस तालिका में सभी आंकड़े घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में मात्रा के मामले में वृद्धि के संबंध में स्वतः स्पष्ट हैं। इसके अलावा, नियोजित पूंजी पर आय ने क्षति की पूरी अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि दर्शायी है। वास्तव में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में यह बहुत अधिक (लगभग 9 गुणा) है।

मालसूची

74. संबद्ध वस्तुओं के माल भंडार से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
औसत भंडार	एम3	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	142	105	269
प्रति दिन उत्पादन	दिवसों की सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	109	124	132
उत्पादन दिवस की संख्या के अनुसार माल भंडार	दिनों की सं.	5	7	5	11

75. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के औसत भंडार में हाल में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।
76. दिवसों की औसत संख्या जिसके लिए घरेलू उद्योग उत्पादन को रोक रहा था, की भंडार में गणना की गई थी। यह देखा गया है कि भंडार में उत्पादन के दिवसों की संख्या क्षति के अवधि के दौरान लगभग 5 से 7 दिनों तक रोकी गई है, इसे जांच की अवधि में बढ़ाकर 11 दिवस तक कर दिया गया है। इसे अत्यधिक नहीं माना जा सकता।

रोजगार और मजदूरी

77. रोजगार और मजदूरी के संबंध में स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	105	106	113
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	145	260	230
प्रति कर्मचारी मजदूरी	रु./ सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	138	245	203

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई मजदूरी में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक वृद्धि हुई है।

उत्पादकता

79. नीचे दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन के मामले में उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 17 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
उत्पादन (मी. टन)	एम3	***	***	***	***
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
उत्पादन/ कर्मचारी	मी. टन/ सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	104	117	117

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता से संबंध में आंकड़ों में क्षति की पूरी अवधि के दौरान सतत् रूप से सुधार हुआ है।

वृद्धि

वृद्धि	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
वर्ष दर वर्ष उत्पादन	%	-	9	13	7
वर्ष दर वर्ष घरेलू उद्योग की बिक्री	%	-	9.3	13.0	6.9
वर्ष दर वर्ष लाभ एवं हानि	%	-	61	279	31
वर्ष दर वर्ष घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	-	2.71	1.14	-0.51

81. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि मांग में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग ने लाभ में वृद्धि, सहज नकदी का प्रभाव और निवेश पर आय में वृद्धि की आशा की थी। हालांकि, घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण उसे अपेक्षित स्तर तक ले जाने में सक्षम नहीं था।

82. यह विश्लेषण दर्शाता है कि वर्ष दर वर्ष घरेलू उद्योग की बिक्री में 2015-16 में आपवादिक वृद्धि के साथ वृद्धि हुई है।

पाटन का आकार :

83. पाटन का आकार उस सीमा का एक संकेतक है जिस सीमा तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध देशों में से दो देशों की तुलना में निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है।

पूँजी निवेश प्राप्त करने की क्षमता :

84. घरेलू उद्योग द्वारा सत्यापन योग्य कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही रिकार्डों पर यह उपलब्ध है जिससे यह आशय निकाला जा सके कि इस क्षेत्र में भावी निवेश संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण नष्ट हो सकती है जो किसी भी मामले में कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत से 7 प्रतिशत (क्षति की अवधि के दौरान का रेंज) होता है।
85. घरेलू उद्योग की इस क्षेत्र के लिए पूँजी निवेश प्राप्त करने की क्षमता संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो सकती है।

क्षति के संबंध में निष्कर्ष

86. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के संबंध में और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच किए जाने के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। आयातों में आंशिक वृद्धि भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत की तुलना में देखी गई है।
87. यह जांच दर्शाती है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए भारत में अतिरिक्त मांग है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री प्राप्ति से कम है। घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है।

क्षति मार्जिन का आकार

88. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना नीचे दिए गए अनुसार जांच की अवधि के दौरान क्षति के मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों की पहुंच मूल्य से की गई है :-

क्षति मार्जिन का आकार

क्र. सं.	देश	उत्पादक/ निर्यातक	एन आई पी (यू एस डॉलर/ एम3)	पहुंच मूल्य (यू एस डॉलर/ एम3)	क्षति मार्जिन (यू एस डॉलर/ एम3)	क्षति मार्जिन %	रेंज %
1	चीन गणराज्य	सभी निर्यातक/ उत्पादक		***	***	***	20-30%
2	संयुक्त अरब अमीरात	मैसर्स जिप्समना (एल. एल. सी.), दुबई	***	***	***	***	0-10%
		कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	15-25%

पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना**घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

89. घरेलू उद्योग द्वारा वर्तमान जांच की अवधि के दौरान पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में किए गए अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया अनुरोध निम्नलिखित है :

- i. संबद्ध देशों में निर्यातकों ने संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया है और उनके पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं। इसके अलावा, इस प्रकार के उत्पादकों के पास उपलब्ध आधिक्य क्षमता अपने आप में घरेलू उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता से कई गुणा अधिक है। देश वार उत्पादन क्षमता और अतिरिक्त क्षमता नीचे दिए गए अनुसार है :

ii.

देश	क्षमता	अनुमानित निर्यात योग्य क्षमता	घरेलू उद्योग की क्षमता के % के रूप में क्षमता
संयुक्त अरब अमीरात	1166250	816250	167%
इंडोनेशिया	1925000	500000	275%
चीन	22050000	6615000	3155%
थाईलैंड	2600000	1575000	372%

दक्षिण अफ्रीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन ने इण्डोनेशिया और थाईलैंड से जिप्सम प्लास्टर बोर्ड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को सतत् रूप लगाये रखने की सिफारिश की है।

iii. दक्षिण अफ्रीकी आयोग द्वारा शुल्कों को सतत् रूप से लगाये रखना स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि इण्डोनेशिया और थाईलैंड के निर्यातक न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी पाटन प्रथाओं में लिप्त हैं।

iv. इन देशों की पाटन प्रथाएं इस तथ्य के साथ साथ हो रही हैं कि इन देशों के पास भारी मात्रा में निर्यात योग्य क्षमताएं हैं और आगे यह इस बात की पुष्टि करता है कि यदि शुल्कों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तब संबद्ध देशों से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार बार होने की हर संभावना है।

v. वर्तमान पाटन और क्षति मार्जिन का मौजूद होना अपने आप में यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को बहुत अधिक क्षति होना तय है यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाए।

उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

90. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन और क्षति की संभावना की जांच करने के लिए किया गया अनुरोध और इस प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :

i. घरेलू उद्योग यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि पाटन अथवा क्षति की कोई संभावना है क्योंकि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के पैरा (vii) में उल्लेख किए गए वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में सभी मानदण्डों को इस मामले में पूरा नहीं किया गया है।

ii. केवल क्षमता होना क्षति की संभावना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आवेदक से यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि इन निर्यातकों के पास इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमता की मौजूदगी के फलस्वरूप भारत में उत्पादों का पाटन होगा। हालांकि, आवेदक इस प्रकार के किसी आरोप को सिद्ध करने में असफल रहे हैं और इस कारण से इस प्रकार का कोई आरोप संभावना संबंधित मानदण्डों के अंतर्गत सही साक्ष्य नहीं बनते हैं।

iii. जबकि वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीकी जांच के संबंध में मैसर्स जिप्समना कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, फिर भी यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस प्रकार का कोई शुल्क संयुक्त अरब अमीरात से किए गए आयातों पर नहीं लगाया गया था। यह इस बात को सिद्ध करता है कि वस्तुओं के पाटन की प्रथा में लिप्त होने का दोषी संयुक्त अरब अमीरात से उत्पादकों को अन्य न्यायाधिकारों में भी नहीं पाया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

91. प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध II (vii) के संबंध में वास्तविक क्षति के खतरे का विशिष्ट उल्लेख करते हुए पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के तर्क की जांच की है। निरमा लिमिटेड बनाम संघ सरकार 2017 (346) ई. एल. टी 328 (गुज.) के साथ पठित इस नियमावली के अनुबंध II का नियम (vii) के संबंध में निर्णय 13/12/2016 को लिया गया।

(क) वास्तविक रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि का अत्यधिक दर।

92. जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों के संबंध में दिए गए तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी को निर्यातकों से जांच की अवधि के पश्चात सूचना प्राप्त नहीं हुई है और साथ ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

93. इसके अलावा जांच की अवधि के पश्चात के संबंध में सूचना, आयात आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस कारण से घरेलू उद्योग ने समर्थन संबंधी साक्ष्य के साथ जांच की अवधि के पश्चात संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन को जारी रहने के तथ्य को सिद्ध नहीं किया है। इसके अलावा अनुरोध में दिए गए क्षमता संबंधी आंकड़ों में माप की इकाई का अभाव है जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की क्षमताओं का अनुमान घरेलू उद्योग द्वारा लगाया गया है।

94. इसके अलावा, यह तर्क कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से सतत पाटित आयातों के कारण क्षति होती रहेगी, वर्तमान मामले में निम्नलिखित कारण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है : (क) वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग क्षति के विश्लेषण और प्रमुख आर्थिक मानदण्डों की जांच के संबंध में पूर्व पैराग्राफ से जिसे देखा जा सकता है, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को आर्थिक मानदण्डों के किसी भी मानदण्ड पर क्षति नहीं उठानी पड़ रही है। (ख) कोई भी सत्यापन योग्य दस्तावेज जांच की अवधि के बाद की अवधि क्षति का दावा करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) किसी अतिरिक्त निर्यात को शामिल करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से बढ़े पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से मुक्त रूप में निपटान योग्य अथवा कोई आसन्न, पर्याप्त वृद्धि।

95. वास्तविक क्षति के खतरे की जांच करने के लिए इस मानदण्ड में भारतीय बाजार में निपटान योग्य मात्रा के मार्ग परिवर्तन की संभावना की तलाश करने के लिए मौजूदा अतिरिक्त क्षमताओं और क्षमतावर्धन, यदि कोई हो, का मूल्यांकन अपेक्षित है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों को पहले से ही बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, यह उत्पादक अनेक देशों में इस उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के मामले में कीमतों से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है, और इस प्रकार से यह पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने की स्थिति में भारत में इन निर्यातों के मार्ग परिवर्तन की संभावना को दर्शाता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने मौजूदा अतिरिक्त क्षमताओं के संबंध में और भारतीय बाजार में बढ़े हुए पाटित निर्यातों की परिणामी संभावना पब्लिक संभाव्यता के संबंध में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य और सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को उसका साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया था। इस संबंध में भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) क्या आयात उन कीमतों पर हो रहा है जिसका घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक निराशाजनक अथवा दबावकारी प्रभाव होगा और इससे आगे आयातों के लिए संभावित रूप से मांग में वृद्धि होगी।

96. भारत में वर्तमान पहुंच मूल्य पर, केवल दो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के मामले में पाटनरोधी शुल्क के बिना जांच की अवधि के दौरान कीमत में कटौती हो रही है।

(घ) वस्तुओं के माल भंडार की जांच की जा रही है।

97. रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों में उन वस्तुओं के माल भंडार जिसकी जांच की जा रही है, के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य निहित नहीं है।

(ङ) भारतीय बाजार की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता

98. आयात कीमत जिस पर संबद्ध वस्तुओं का आयात संबद्ध देशों द्वारा भारत में किया जा रहा है, की जांच की अवधि के पश्चात का लेन देन वार आयात आंकड़ा पाटन के जारी रहने की संभावना का संकेतक है। उसका कोई ब्यौरा न तो घरेलू उद्योग द्वारा अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

(च) इस उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता के संबंध में घरेलू उद्योग और भारतीय बाजार की जोखिम संबंधी संभावना

99. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारतीय बाजार बहुत अधिक कीमत संवेदनशील है। उपभोक्ता अपनी खरीद के बारे में निर्णय कीमत पर अत्यधिक विचार करते हुए करते हैं। ऐसा मामला होने के कारण इस बाजार में संबद्ध देशों से इस प्रकार की कम कीमत पर आयातों की उपलब्धता से घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए तथा उपर्युक्त में चर्चा किए गए वर्तमान पाटन और पाटन की संभावना तथा क्षति के मानदण्डों पर विचार करने के बाद यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने उस उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता पर कोई टिप्पणी नहीं की है जो घरेलू उद्योग को जोखिम के योग्य बनाए।

अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

100. धारा 9क (5) के अंतर्गत कार्यकारी से यह अपेक्षित है कि वह पाटन और क्षति की संभावना तथा इस बात पर विचार किए बिना उनको जारी रखने की आवश्यकता के बारे में जांच करे कि क्या समीक्षा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात हुआ है अथवा नहीं।

101. इस बात की जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य मानदण्डों का घरेलू उद्योग क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था। इसे नीचे दिए गए अनुसार नोट किया गया :

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

102. संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात बहुत अधिक है जैसा कि डी जी सी एंड आई एस से प्राप्त लेन देन वार आंकड़ों से प्रकट हुआ है। यह पैटर्न क्षति की पूरी अवधि के दौरान देखा गया है। जांच की अवधि के दौरान कुल आयातों का लगभग 78 प्रतिशत मात्रा में ये आयात कथित रूप से अधिक हुए हैं।

(ख) मांग का संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

103. क्षति की पूरी अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में एक सतत वृद्धि हुई है।

(ग) प्रौद्योगिकी में विकास :

104. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधक प्रथाएं

105. कोई व्यापार प्रतिबंधक प्रथा नहीं है जो घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। कच्चा माल तथा संबद्ध वस्तु इस देश में मुक्त रूप से आयात के योग्य हैं।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

106. कार्यकारी द्वारा उनके घरेलू प्रचालन को ध्यान में रखकर ही क्षति का विश्लेषण किया गया है। इस कारण से निर्यात बाजार में कार्य निष्पादन ने क्षति के वर्तमान विश्लेषण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

107. यह नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन तथा प्रतिदिन उत्पादन के मामले में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में इस अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है।

प्रकटन पश्चात विवरण

108. प्रकटन के बाद के चरण में उठाये गये मुद्दों को इस जांच के दौरान पूर्व में पहले ही उठाया गया है और उसका समाधान भी उपर्युक्त रूप से किया गया है। हालांकि, स्पष्टता के वास्ते इन अनुरोधों को जिसे संदर्भ के उपयुक्त पाया गया और जिसका वास्तविक आधार है, सारांश तथा उसका फिर से समाधान नीचे दिए गए अनुसार किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में अलग अलग पैरा में इन मुद्दों का समाधान किया गया है :

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

109. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का सारांश नीचे दिए गए अनुसार है :

- i. प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है।
- ii. प्राधिकारी ने सही ढंग से इस बात का विश्लेषण नहीं किया गया है कि घरेलू उद्योग पर कीमत का कोई दबाव नहीं है।

- iii. पाटनरोधी शुल्क को शामिल करने के साथ, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से कीमत में सकारात्मक कटौती हुई है।
- iv. चीन के मामले में 35 प्रतिशत तक और संयुक्त अरब अमीरात के मामले में 20-30 प्रतिशत तक कीमत में गंभीर कटौती हुई है।
- v. प्रकटन विवरण में इस बात का उल्लेख नहीं था कि क्यों कीमत में कटौती पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुंच कीमत के आधार पर नहीं की जानी चाहिए थी।
- vi. कोई टिप्पणियां उपलब्ध कराने में असफल होना क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने गैर क्षतिकारक कीमत का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।
- vii. प्राधिकारी चीन और संयुक्त अरब अमीरात के मामले में सकारात्मक और वास्तविक कीमत कटौती की उपेक्षा करते हैं।
- viii. निर्दिष्ट प्राधिकारी का वर्तमान विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग का सुधार किया गया कार्य निष्पादन पाटनरोधी शुल्क के कारण ही लागू है।
- ix. पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य को उसी सूचीबद्ध संख्याओं में दर्शाया गया है जो एक टंकण संबंधी त्रुटि है।
- x. सही संख्याओं तथा इस प्रकार से ठीक की गई संख्याओं पर विश्लेषण के साथ एक नया प्रकटन विवरण जारी करना।
- xi. क्षमता में परिवर्तन को क्षमता में वृद्धि के रूप में नहीं कहा जा सकता है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रमुख कारणों (क) इस उत्पाद के वजन में कमी के कारण (ख) बाधाओं को दूर करने के रूप में उत्पादन में वृद्धि क्योंकि इस उत्पाद के वजन में कमी के फलस्वरूप लाइन स्पीड में वृद्धि हुई है, के आधार पर हुआ है।
- xii. क्षमता में 16 प्रतिशत तक की वृद्धि का आशय यह होगा कि जांच की अवधि में 48 प्रतिशत की वृद्धि आधार वर्ष से तुलना किए जाने पर होगी और मामला ऐसा नहीं है। इस कारण से प्रकटन विवरण में की गई टिप्पणियां सही नहीं हैं और नया विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।
- xiii. पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो रही है और इस कारण से वर्तमान क्षति के अलावा यदि इन शुल्कों को समाप्त कर दिया जाए तब भविष्य में क्षति होने की संभावना है।
- xiv. इस विश्लेषण में इस बात पर विचार नहीं किया गया कि जांच की अवधि के दौरान किए गए सभी आयात मुख्य रूप से, साउदी अरब और थाईलैण्ड से हुआ है।
- xv. तालिका यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयातों और बाजार हिस्से में क्षति की पूरी अवधि जिसमें पहुंच मूल्य में कमी आई है, वृद्धि हुई है।
- xvi. कुल आयातों में अन्य देशों के बाजार हिस्से में भी संबद्ध देशों से आयातों में बाजार हिस्से में वृद्धि के मामले में तमाम अनुपात में वृद्धि हुई है।
- xvii. जहां तक पहुंच मूल्य के विश्लेषण पर विचार किया गया है, प्रकटन विवरण में की गई टिप्पणियां त्रुटिपूर्ण हैं।
- xviii. पैरा 83 में प्राधिकारी का विश्लेषण सही नहीं है और यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
- xix. निर्यातकों ने जांच की अवधि के बाद आंकड़े उपलब्ध कराने से इनकार किया है और उन्हें अभी भी सहयोगी निर्यातकों के रूप में विचार किया जा रहा है।
- xx. यह उल्लेख करना सही नहीं है कि घरेलू उद्योग ने पाटन के जारी रहने को सिद्ध नहीं किया है क्योंकि जांच की अवधि के पश्चात के आयात आंकड़ों को दायर नहीं किया गया है।
- xxi. जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े संभावना के विश्लेषण तक सीमित हैं। पाटन का जारी रहना अपने आप में प्राधिकारी द्वारा सिद्ध हो जाता है।
- xxii. कोई अनुरोध अथवा निर्देश पाटनरोधी महानिदेशालय द्वारा घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए नहीं किए गए थे।
- xxiii. पैरा 44 का संदर्भ लेते हुए घरेलू उद्योग ने नोट किया कि प्राधिकारी ने स्वयं इस बात का निर्धारण किया गया, किए गए क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग को पाटन से हुई क्षति को दर्शाता है। इस कारण से यह बात समझ से परे है कि प्राधिकारी ने इस प्रकार से इस बात का निर्धारण किया कि घरेलू उद्योग को किसी आर्थिक मापदण्डों के संबंध में क्षति नहीं हो रही है।
- xxiv. सुनवाई के पश्चात घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी महानिदेशालय से यह अनुरोध किया कि वह जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े प्राप्त करने के लिए अधिकरण दें और इन आंकड़ों की प्रतीक्षा किए बिना प्रकटन विवरण जारी किया गया था।

- xxv. हालांकि, कोई कानूनी अथवा तार्किक अपेक्षा नहीं है कि जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों के आधार पर इन संभावनाओं तय किया जाना है।
- xxvi. क्षमताओं के लिए माप की इकाई का अनुमान एम3 के रूप में लगाया गया है और इसका उल्लेख आवेदन में किया गया है और उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नोट किया जाना चाहिए।
- xxvii. निर्यातक के प्रश्नावली के उत्तर का उचित विश्लेषण अपने आप में इन उत्पादकों के पास मौजूद अतिरिक्त क्षमताओं की जानकारी से देगा।
- xxviii. किसी भी निर्यातकों अथवा हितवद्ध पक्षकारों ने संबद्ध देशों से अतिरिक्त क्षमताओं के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्य का खंडन किया है।
- xxix. पैरा 98 का संदर्भ लेते हुए घरेलू उद्योग ने नोट किया कि प्राधिकारी सही नहीं हैं क्योंकि प्राधिकारी सहयोग करने वाले निर्यातकों से उनके उत्तरों के भाग II के माल भंडार से संबंधित सूचना का निर्धारण कर सकते हैं।
- xxx. घरेलू उद्योग बाजार इनपुट से इस बात की जानकारी प्राप्त कर पाए हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत में जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों में और आगे गिरावट आई है।
- xxxi. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से इन निर्यातों के विरुद्ध अन्य देशों द्वारा लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के संबंध में अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया।

निर्यातकों / उत्पादकों और अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किया गया अनुरोध

निर्यातकों / उत्पादकों और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

110. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां नीचे दिए गए अनुसार हैं :

- i. निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर उत्पादन की लागत और घरेलू एवं अन्य कीमतों का पूर्ण साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया था लेकिन उस पर ध्यान दिए बिना प्राधिकारी ने इस उत्तर की उपेक्षा की थी और यह निष्कर्ष निकाला कि पाटन के फिर से होने की संभावना है क्योंकि इसे दक्षिण अफ्रीका के प्राधिकारियों द्वारा लगाया गया है।
- ii. प्रकटन विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संबद्ध प्रश्नों के आयातों के संबंध में कोई वर्तमान पाटन अथवा क्षति होती है और न ही पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की कोई संभावना है।
- iii. अगली पीढ़ी मानक बोर्ड को भी सिर्फ इस कारण से बाहर किया जा सकता है कि उसका निर्माण अथवा आयात भारत में नहीं किया जाता है। इसमें विशेष लक्षण ही निहित हैं।
- iv. विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने वाले संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैण्ड और इण्डोनेशिया के याचिकाकर्त्ता के संबंधित पक्षकारों के कारण, याचिकाकर्त्ता इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग नहीं हैं।
- v. प्राधिकारी द्वारा नोट किए गए निष्कर्ष से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि थाईलैण्ड से किसी प्रकार का पाटन नहीं हुआ है।
- vi. प्राधिकारी से यह निष्कर्ष की संचयी आंकलन के उद्देश्य से, पाटन न किए गए आयातों को क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से बाहर रखा जाना चाहिए, से सहमति।
- vii. थाईलैण्ड से पाटित आयातों के न होने का निष्कर्ष यह होता है कि थाईलैण्ड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए आयातों से वर्तमान में कोई पाटन अथवा क्षति नहीं हुई है।
- viii. जैसा कि प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया है सभी आर्थिक मापदण्ड भी यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं उठानी पड़ रही है और यह अपनी स्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार लाने में सक्षम रहा है।
- ix. संभावना के प्रथम कारक के संबंध में, क्षति के अवधि के दौरान और न ही जांच की अवधि के पश्चात थाईलैण्ड से भारत में कोई आयात हुआ है। इस प्रकार से किसी बड़े हुए आयात की संभावना का कोई संकेत नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की कीमतों पर किसी प्रकार का दबावकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव नहीं पड़ा है।
- x. स्वतंत्र रूप से बिक्री किए जाने योग्य क्षमता के संबंध में, एस जी आई एस बी की 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग दर है और इसके पास स्वतंत्र रूप से बिक्री किए जाने योग्य क्षमता नहीं है। जहां तक एस जी आई एस के का संदर्भ लिया जाता है, एक न्यूनतम स्वतंत्र क्षमता हो सकती है, जिसका उपयोग थाईलैण्ड और अन्य वैकल्पिक बाजारों में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इस कारण से थाईलैण्ड से संबद्ध वस्तुओं के आयात में कोई वास्तविक वृद्धि का भविष्य में कोई खतरा नहीं है।
- xi. दक्षिण अफ्रीका के प्राधिकारी के रिपोर्ट इस जांच में जांच की अलग अलग अवधि होने के कारण विश्वास नहीं किया जा सकता है, यह निर्धारण प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर किया गया था और थाईलैण्ड से निर्यात की मौजूदगी थी, जो वर्तमान जांच में नहीं है।

- xii. प्राधिकारी ने इस बात पर सहमत होने के बावजूद जांच को समाप्त नहीं किया कि पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने के लिए कोई प्रथम दृष्टया औचित्य नहीं है।
- xiii. इस याचिका में सटीकता और कमियां मौजूद थी क्योंकि इस आवेदन अधिकतर रूप में स्वतः सिद्ध करने वाली और विरोधाभास विवरण निहित थे और अगोपनीय पाठ पर्याप्त नहीं थे और यह सटीक नहीं था।
- xiv. संयुक्त अरब अमीरात में संबंधित पक्षकार की उपस्थिति याचिकाकर्ता को संयुक्त अरब अमीरात में अत्यधिक क्षमताओं का दावा करने से रोकना चाहिए।
- xv. प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि ये गोपनीयता के मुद्दे की फिर से जांच करें।
- xvi. यद्यपि प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि इन आयातों में स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है फिर भी इसे मांग में वृद्धि, घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि और गैर संबद्ध देशों के आयातों में वृद्धि के आलोक में देखा गया है।
- xvii. प्राधिकारी ने नोट किया है कि यह आरोप कि घरेलू उद्योग कम कीमत पर हो रहे आयातों के कारण कीमत में वृद्धि नहीं कर सका, सही नहीं है। हालांकि वह गैर संबद्ध आयातों के कारण हुआ है जैसा कि आयातों के तुलनीय सी आई एफ आयात कीमत और संबद्ध देशों से आयातों से अपेक्षाकृत अधिक पहुंच कीमत से सिद्ध की जा सकती है।
- xviii. घरेलू उद्योग इस संबंध में अपनाई गई स्थिति की संबद्ध देशों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, समर्थन किए जाने योग्य नहीं है : घरेलू उद्योग धारित बाजार हिस्सा स्थिर रहा है (प्रथम दो वर्षों में 65-63 प्रतिशत और पिछले दो वर्षों में 61-60 प्रतिशत)।
- xix. अन्य देशों से आयातों में मांग में वृद्धि के साथ साथ तेजी से वृद्धि हुई है।
- xx. घरेलू उद्योग को यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि अतिरिक्त क्षमता के मौजूद होने के कारण भारत में सघन रूप से पाटन हुआ है। प्राधिकारी ने इसे नोट कर लिया है।
- xxi. विचाराधीन उत्पाद के रूप में पी सी एन वार विश्लेषण के लिए आवश्यकता क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री अलग अलग रूपों में और अलग अलग मोटाई में किया जा रहा है और उसकी अलग अलग लागत और कीमतें हैं।
- xxii. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि ये कृपया संबद्ध और गैर संबद्ध देशों से एक ही प्रकार के बोर्ड के लिए तुलनीय कीमतों को नोट करें।
- xxiii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में क्षति की अवधि की तुलना में बहुत अधिक सुधार हुआ है।
- xxiv. घरेलू उद्योग को चीन से आयातों के संबंध में क्षति हुई है।
- xxv. स्वीकार की गई क्षमताओं के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात के उत्पादकों ने दक्षिण अफ्रीका के बाजार में पाटन का सहारा नहीं लिया है जो यह दर्शाता है कि अपेक्षाकृत कम कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में भारत में बढ़े हुए आयातों की संभावना नहीं है।
- xxvi. गैर संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास बहुत अधिक क्षमताएं भी हैं और भारत में निर्यात की वर्तमान मात्रा उनकी क्षमताओं की तुलना किए जाने पर बहुत मामूली है।
- xxvii. यदि गैर संबद्ध देशों में विदेशी उत्पादकों को भारतीय बाजार आकर्षक के रूप में नहीं मिल रहा हो, तब ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यो संबद्ध देशों के उत्पादक भारतीय बाजार को आकर्षक पाएंगे।

प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्रकटन के बाद के चरण में उठाये गये अधिकांश मुद्दों की जांच उपर्युक्त संबंधित पैरा में किया गया है। नुटियों एवं विलोपों उसका उल्लेख प्रकटन विवरण में किया गया है, जो जहां भी आवश्यक हुआ ठीक कर लिया गया है। प्रकटन के बाद के विवरण में दिए गए तर्कों के संबंध में प्राधिकारी के उत्तर का सारांश नीचे दिया गया है :

- i. प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को इस प्राधिकारी की सतत् परंपराओं के अनुसार पर्याप्त समय की अनुमति दी गई है। यह भी नोट किया जाता है कि प्रकटन विवरण में अधिकांश आंकड़े/ सूचना याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के संबंध में है और इसलिए इन्हें घरेलू उद्योग की जानकारी के रूप में माना गया है। घरेलू उद्योग से केवल यह आग्रह किया गया था कि वे इस प्रकार की सूचना, प्रकटन विवरण में कथनों पर विचार करें और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।
- ii. प्राधिकारी इस बात से सहमत नहीं हैं कि क्षति के संबंध में अथवा क्षति की संभावना के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा किए सभी अनुरोधों पर प्रकटन विवरण और अंतिम जांच परिणामों में समुचित रूप से विचार किया गया है। हालांकि, जहां केवल टिप्पणियों को बिना सहायक साक्ष्य दोहराया गया है, इस

प्रकार की टिप्पणियों को आवश्यक तथ्यों के रूप में नहीं माना गया है। वास्तव में घरेलू उद्योग ने क्षति के संबंध में विरोधीभासी तर्कों को प्रस्तुत नहीं किया है। इस बात का तर्क देते समय की घरेलू उद्योग को इन आयातों से क्षति हुई है, उसकी पुष्टि तथ्यों के साथ नहीं की गई है और वह घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के संबंध में रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल भी है। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखाया है, जहां प्रकटन विवरण में अपनाए गई सूचना/ आर्थिक मापदण्ड उससे वास्तविक रूप से अलग हो, जिसका दावा याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है। प्राधिकारी वस्तुनिष्ठ रूप में इस याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई विभिन्न सूचनाओं की जांच की है और वह वर्तमान मामले में लागू विभिन्न कानूनी प्रावधानों के अनुसार है।

- iii. याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि कीमत में कटौती पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के बाद सकारात्मक है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इन अनुरोधों के अलावा विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है। पाटनरोधी शुल्क को शामिल करने के बाद संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत गैर संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा, गैर संबद्ध देशों से आयात की मात्रा संबद्ध देशों से की गई आयात की मात्रा से पर्याप्त रूप से अधिक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता इस बात का दावा नहीं कर सकता था कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण क्षति हुई है और गैर संबद्ध देशों से आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा गैर संबद्ध देशों से किए गए आयातों की तुलना में संबद्ध देश के किए गए आयातों की कीमत और मात्रा संबंधी मापदण्डों को देखते हुए, घरेलू उद्योग पर कथित कीमत का दबाव संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं हो सकता था। यह गैर संबद्ध देशों से आयातों के कारण हो सकता था। याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने के लिए कोई आंकड़े/ सूचना/ विश्लेषण नहीं उपलब्ध कराया है कि गैर संबद्ध देशों से आयातों के कारण अपेक्षाकृत कम कीमत पर तथा मात्रा के मामले में बहुत अधिक होने के बावजूद कीमत पर दबाव नहीं बना।
- iv. घरेलू उद्योग के बिक्री संबंधी मापदण्डों के संबंध में तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री क्षति की अवधि की तुलना में बढ़ गई थी। इसके अलावा, गैर संबद्ध देशों से आयात क्षति की अवधि की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया जबकि उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से आयात में केवल 5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इस प्रकार से, घरेलू बिक्री में कथित गिरावट संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण सिद्ध नहीं की जा सकती।
- v. आयात के पहुंच कीमत में कथित त्रुटि के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचीबद्ध आंकड़ों को प्रकटन विवरण में सही रूप से प्रस्तुत किया गया है।
- vi. याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि क्षमताओं में कोई वृद्धि नहीं हुई थी और इन क्षमताओं में केवल एक परिवर्तन हुआ था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने अपने आप इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया जिसमें इसने क्षति की अवधि की तुलना में क्षमता में वृद्धि को दर्शाया है। क्या क्षमता में इस प्रकार की वृद्धि उत्पादन सुविधाओं को बढ़ाने अथवा बाधाओं को दूर करने के कारण अथवा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के कारण अथवा बढ़ी हुई कार्यक्षमताओं के कारण हुई है। इस बात के संबंध में निर्णय करने में कोई महत्व नहीं रखता है कि क्या क्षमताओं इस अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है।
- vii. जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों का संदर्भ जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के आधार पर इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संभावना की संभावित दावे के संबंध में है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने किसी पक्षकार को जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए निर्देश नहीं दिए हैं। यह निर्णय करना हितबद्ध पक्षकारों के लिए है कि क्या वे अपने मामले को आगे बढ़ाने जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों पर विश्वास करना चाहते हैं। न तो घरेलू उद्योग और न ही निर्यातकों ने जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों के आधार पर अपने पक्ष में तर्क दिए हैं और तदनुसार प्राधिकारी ने जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों के आधार पर इस मामले के गुण दोषों की जांच नहीं की है। निर्यातकों से जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों के प्राप्त न होने के संबंध में टिप्पणियां करते समय घरेलू उद्योग ने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि घरेलू उद्योग ने भी जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों के आधार पर कोई दावा नहीं किया है।
- viii. इस तर्क के संबंध में की याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने वास्तव में जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रयास किए थे और प्राधिकारी ने उचित समय नहीं प्रदान किया, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए जांच की इस अवधि के बाद की 6 महीने की अवधि को संतोषजनक के रूप में मानते हैं। वर्तमान मामले में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि जून 2017 में समाप्त हो गई और प्राधिकारी ने मार्च 2018 में सुनवाई आयोजित की थी। यह हितबद्ध पक्षकारों के लिए खुला हुआ था कि वे जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े प्राप्त करें और उसके आधार पर अपने मामले को आगे बढ़ाएं। हालांकि, याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने सुनवाई के चरण तक जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े एकत्रित करने में प्रयास नहीं किया और अब प्रकटन विवरण जारी करते समय घरेलू उद्योग को समुचित समय नहीं देने के लिए प्राधिकारी पर दोषारोपण करने की कोशिश की है। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों के संबंध में पर्याप्त तर्क दिए हैं, यह भी तर्क दिया गया है कि जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े संभावना की जांच के लिए आवश्यक भी नहीं हैं और इस संभावना को वर्तमान क्षति की अवधि के लिए आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार से एक ओर घरेलू उद्योग ने उन आधारों पर निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को अस्वीकार किए जाने की मांग की है कि वे जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े उपलब्ध कराने में असफल हो गए हैं जबकि दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के

पश्चात के आंकड़ों की आवश्यकता पर सवाल खड़ा किया है। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए विरोधाभासी कथनों से प्राधिकारी याचिकाकर्ता के वर्तमान तर्क को वस्तुनिष्ठ तरीके से जांच करने के लिए बाध्य होता है।

- ix. प्रकटन विवरण के पैरा 44 के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने सावधानीपूर्वक प्रकटन विवरण को पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया है। प्रकटन विवरण के पैरा 44 में की गई स्वीकारोक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई जांच की प्रकृति और न कि प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष के संबंध में है। इस तथ्य से यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि इस पैरा को प्राधिकारी द्वारा जांच के प्रारंभ में और क्षति संबंधी विभिन्न मापदण्डों के विश्लेषण के पूर्व भी प्रस्तुत किया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राधिकारी क्षति संबंधी मापदण्डों का विश्लेषण किए बिना भी घरेलू उद्योग को क्षति के होने के संबंध में निष्कर्ष नहीं निकाला होता। इस प्रकार से पैरा 44 में की गई जांच, जांच की प्रकृति मात्र है और उसे प्राधिकारी द्वारा किया गया है और यह इस प्राधिकारी द्वारा क्षति के संबंध में निकाले गए निष्कर्ष को नहीं दर्शाता है।
- x. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि कीमत में सकारात्मक कटौती और क्षति मार्जिन के मौजूद होने का अपने आप में यह अर्थ होता है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। हालांकि, प्राधिकारी यह मानते हैं कि उसका कोई कानून और वास्तविक आधार नहीं है। यह तथ्य की क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, का निर्धारण अनुबंध 11 के प्रावधानों के संबंध में किया जाना अपेक्षित है और केवल कीमत में सकारात्मक कटौती, क्षति मार्जिन का होना अपने आप में यह अर्थ नहीं होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। खासकर, प्राधिकारी इस पर विचार करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग सतत क्षति हुई है, को मानने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट आई है।
- xi. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत, निर्यातकों ने अतिरिक्त क्षमताओं के सांकेतिक मात्र के रूप में क्षमताओं पर विश्वास करने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे का खंडन किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के पास अतिरिक्त क्षमताओं के साथ तमाम क्षमताएं हैं।
- xii. याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान पाटन का होना पाटन की संभावना अथवा उसके पीछे होने पर विचार करने के लिए आवश्यक नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन स्थितियों में जहां कोई वर्तमान आयात नहीं हुआ है और इसलिए वर्तमान पाटन नहीं हुआ है, याचिकाकर्ता से यह अपेक्षित है कि वह देश में इस उत्पाद के पाटन के फिर से होने की संभावना को स्थापित करे। याचिकाकर्ता सहायक साक्ष्य के साथ यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि इस देश में पाटन के फिर होने की संभावना है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता को 21/3/2018 को एक पत्र भेजा गया था :

“संदर्भ : इन प्रतिउत्तरों का पैरा 8 जिसका संभावना को सिद्ध करने के लिए मापदण्डों के रूप में संदर्भ लिया गया है। क्या आप कृपया उन साक्ष्यों (दस्तावेजों का संदर्भ जिन्हें प्रस्तुत किया गया है) की सूची दे सकते हैं जो आपने (1) बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताएं (2) निर्यात उन्मुखीकरण (3) पाटन व्यवहार (4) आक्रामक कीमत निर्धारण नीति के संबंध में उपलब्ध कराया है”

उसके संबंध में याचिकाकर्ता से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सार्वजनिक याचिका में इस मेल का रख दिया गया है।
- xiii. कारणात्मक संबंध की जांच की आवश्यकता के संबंध में, प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षाओं में भी कारणात्मक संबंध की जांच सतत रूप से की है। यह माना गया है कि घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित है कि वह सिद्ध करे कि पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने से घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग को सतत क्षति नहीं हुई है, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति और वर्तमान पाटन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। इस कारण से प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में सतत पाटन की संभावना के कारण क्षति के फिर से होने की संभावना की जांच की है।
- xiv. अन्य देशों द्वारा संबद्ध देशों से निर्यातों के विरुद्ध लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क उन देशों पर लगाया गया है जिन्होंने भारतीय बाजार में इस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। जबकि, उन देशों जो भारतीय बाजार में इस उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं और जिनमें पाटनरोधी शुल्क से क्षति हो रही है, को इन उपायों द्वारा शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार से अन्य देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने के तथ्य से घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन की संभावना सिद्ध नहीं होती है।

निष्कर्ष

112. याचिका में विभिन्न कथनों में यह दर्शाया गया है कि स्वयं याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि इसे क्षति नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि लगाये पाटनरोधी शुल्क ने घरेलू उद्योग के विकास में तथा आयातों के विरुद्ध आवश्यक संरक्षण प्रदान करने में एक प्रभावी भूमिका निभाई है। इसके अलावा, संबंध देशों से आयातों की मात्रा में मूल जांच की अवधि से लेकर वर्तमान जांच की अवधि के बीच बहुत अधिक गिरावट हुई है।

113. निष्कर्ष का सारांश नीचे दिया गया है :

- i. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक मापदण्डों में सुधार हुआ है।

- ii. घरेलू उद्योग यह दर्शाने में असफल रहे कि क्षति घरेलू उद्योग द्वारा आयातों के कारण हुई है।
- iii. घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के साथ घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के संबंध में अपने दावे की पुष्टि करने में असफल रहे।
- iv. गैर संबद्ध देशों से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आयात हुआ है और इसके कीमत की तुलना की जा सकती है तथा स्वीकार्य रूप से इसके कारण क्षति नहीं हो रही है जिसमें गैर संबंध देशों से आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्री में संबद्ध देशों से आयातों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।

सिफारिशें

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, हानि और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना देने के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये थे। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संबंध में पाटन, हानि और कारणात्मक संबंधों की जांच शुरू करने तथा उसे आयोजित करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि पाटन और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति उस स्थिति में होने की संभावना है जब वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को ऊपर में दिए गए कारणों से और आगे न बढ़ाया जाये, और न ही पाटन आयातों और घरेलू उद्योग को संभावित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है। इस कारण से प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश नहीं करता है।

115. केंद्र सरकार के इस आदेश के विरुद्ध एक अपील जो इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना के कारण हो सकता है सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 19th April, 2018

Subject: Sunset Review of Anti-dumping duty imposed on imports of "Plain Gypsum Plaster Boards", originating in or exported from China PR, Indonesia, Thailand, and UAE.

F. No. 7/8/2017-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof; the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of "Plain Gypsum Plaster Boards", (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Indonesia, Thailand, and UAE (hereinafter referred to as subject Countries). The Authority vide its preliminary findings No. 14/45/2010-DGAD dated the 19th March, 2012, recommended imposition of anti-dumping duties against dumped imports of the subject goods from the Subject countries. Duties were imposed by the Central Government vide custom notification No. 32/2012-Customs (ADD) dated the 7th June, 2012. The Final Findings notification of the Authority was published vide notification No. 14/45/2010-DGAD dated 15th January, 2013. On the basis of the findings, definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from subject countries were imposed by the Department of Revenue vide notifications No. 6/2013-Customs (ADD) dated 12th April, 2013.

1. WHEREAS in terms of Section 9A (5) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.
2. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. Whereas, a petition was filed by M/s Saint-Gobain India Private Limited (hereinafter referred to as 'petitioner') in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of a sunset review of the Anti-dumping duty in force on import of "Plain Gypsum Plaster Boards" for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of

continuation or recurrence of dumping and injury of the subject goods originating in or exported from China PR, Indonesia, Thailand, and UAE.

4. And whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, issued a Notification No. 7/8/2017-DGAD dated 05th June, 2017, published in the Gazette of India, initiating the subject investigations in accordance with the above Rule to examine whether the expiry of the said duties on the import of the above goods originating or exported from the subject countries is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

5. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject countries.

PROCEDURE

6. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

- i. The Authority notified the Embassy of China PR, Indonesia, Thailand, and UAE in India about the receipt of the sunset review of anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
- ii. The Authority issued a public notice dated 05th June, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating sunset review investigation concerning imports of the subject goods.
- iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- iv. The Embassy of the subject countries in India was also requested to advise the exporters/producers from subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from these countries.
- v. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of China PR, Indonesia, Thailand, and UAE in India, known producers/exporters from subject countries and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- vi. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR, (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the AD Rules.
 1. Gypsemna Company (L.L.C), UAE
 2. The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co., Ltd., Thailand
 3. Pt. Siam Indo Gypsum Industry, Indonesia
 4. Pt Petrojaya Boral Plaster board, Indonesia
 5. Shandong Baier Building Materials, China
 6. Linyi Huamei Gypsum Building, China
 7. CNBM International Corporation, China
- vii. In response to the above notification, the following producers/exporters have filed their Questionnaire responses in the above matter. The same has been accepted by the Authority.
 1. M/s Gypsemna Company (L.L.C), UAE
 2. M/s Siam Gypsum Industry (Songkhla) Co. Ltd.
 3. M/s Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co. Ltd.
 4. M/s PT Petrojaya Boral Plasterboard
 5. M/s PT. SIAM-INDO Gypsum Industry
- viii. After the initiation of the investigation, another company namely M/s Knauf LLC, Dubai, UAE had submitted only a letter to the Authority but have not submitted exporter's questionnaire response.
- ix. The Authority also forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the authority) of subject goods in India and

advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):

1. M/s Sastha Senior Building Product
 2. M/s Lafarge Boral Gypsum India Private Limited
 3. M/s Lafarge Boral Gypsum India Pvt
 4. M/s Vikash Trading Company
 5. M/s Total Solutions Building Material Co.
- x. The Authority notes that none of the importers responded to the questionnaire sent by the Authority.
 - xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).
 - xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
 - xiii. The period of investigation is January 2016 to December 2016 (12 months) and for the purpose of injury determination, the period i.e., April 2013 to March 14, April 2014 to March 15, April 2015 to March 16 and the POI will be considered.
 - xiv. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
 - xv. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
 - xvi. The Authority held an oral hearing on 06th March, 2018 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6), which was attended by the representatives of domestic industry and other interested parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were requested to submit their rejoinders thereafter.
 - xvii. Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties.
 - xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
 - xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
 - xx. In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority to the concerned interested parties. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority have been considered in this final finding.
 - xxi. ‘***’ in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - xxii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is

1US\$ = Rs.67.96

PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions by the Domestic Industries

7. The submissions made by domestic industry are as follows:
- i. The present investigation being a sunset review, the scope of the Product under Consideration cannot be changed from what was there in the original investigation.
 - ii. The interested parties have claimed that in addition to the existing exclusions from the scope of product under consideration, Next Generation Standard Board (Next Gen.), is also liable to be excluded, as it is a product not manufactured or imported into India during the POI. In the absence of imports or manufacture in India, no anti-dumping duty can be levied. In this regard, the Domestic Industry submits that the exclusion in the original investigation was provided to certain products on the basis of their physical/technical specifications, usage, substitutability etc. Any exclusion, apart from the ones already there, has to pass the same yardstick. However, if the Authority after examination is of the view that a specific product ought to be excluded on the basis of its physical/technical specifications, usage, substitutability etc., the Domestic Industry does not have any reservations against it.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

8. The submissions made by other interested parties are as follows:
- i. In addition to the existing exclusions from the scope of product under consideration, Next Generation Standard Board (Next Gen.), is also liable to be excluded, as it is a product not manufactured or imported into India during the POI. In the absence of imports or manufacture in India, no anti-dumping duty can be levied.

Examination by the Authority

9. The product under consideration in the present application is “Plain Gypsum Plaster Boards of all thicknesses and dimensions but excluding the following:

- a. Gypsum Boards having water absorption up to and including 5% (Moisture Resistant Boards)
- b. Gypsum Boards having a minimum breaking load of 24 neutrons in the transverse direction and 50 neutrons in the longitudinal direction per millimeter of thickness (Impact Resistant Boards” or “Fire Resistant Boards).
- c. Fire Boards
- d. Fire Heat Boards
- e. Gypsum Ceiling Boards with Moisture Barrier
- f. ECHO Boards
- g. Heat Boards
- h. Anti-modal Boards or Weather Boards
- i. Thermal Boards
- j. Gypsum Ceiling Boards with Aluminium Edges Sealed in White Film

10. The product under consideration is classified under chapter heading 68091100. However, the subject goods are also being imported under tariff headings 68091900. However, Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. Present investigation, being a sunset review of the duty in force, the products under consideration would remain the same as has been defined in the original investigation.

11. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:-

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

12. After considering the information on record, the Authority holds that there is no material difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. Product under consideration produced by the domestic industry is comparable to the imported subject product in terms of physical characteristics, production technology & manufacturing process, functions & uses, product specifications, distribution & marketing. The two are technically and commercially substitutable.

13. The Authority holds that the product manufactured by the domestic industry and the subject goods imported into India from the subject country are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules.

SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

Submissions by the Domestic Industries

14. The submissions made by the domestic industry are as follows:
- i. The request for the sunset review has been filed by M/s Saint-Gobain India Private Limited. The applicant accounts for around 84% of the total domestic production which may be considered as a major proportion of the domestic production of the subject goods.
 - ii. Petitioner has not imported the subject goods from subject country during the POI. Petitioner is not related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration in the subject country. Thus the petitioner is eligible domestic industry under Rules 2(b) and 5(3) of the AD Rules.
 - iii. The interested parties have argued that since the Domestic Industry have related parties in the subject countries, it cannot be considered as a Domestic Industry in terms of Anti-Dumping Rules. In this regard, the Domestic Industry submits that it does not have any related party in any of the subject country, which is engaged in production of the subject goods or exports of the subject goods to India. A declaration regarding the same has already been filed with the petition. The Domestic Industry further submits that the interested parties are trying to divert the attention of the Authority from the substantive facets of the investigation by making fallacious arguments and frivolous accusations.
 - iv. The interested parties have argued that the Domestic Industry has concealed the fact that there are more than two producers of the subject goods in India. They have stated that apart from two producers, specifically mentioned by the Domestic Industry in its petition, there are few other producers of the subject goods in India. In this regard, the Domestic Industry submits that there are indeed few manufacturers who are attempting to put capacities in India for the subject goods. However, to the best knowledge of the Domestic Industry, some of them were in trial run before the POI or were manufacturing the Product under Consideration at very small scale. Owing to the small or nascent operations of these producers, the Domestic Industry, at the time of the initiation, was not in a position to acquire information and data relating to these producers. In any case, the emergence of these new market players itself proves that the anti-dumping duties against the subject countries have been effective. However, owing to the huge excess capacities owned by the exporters from the subject countries, their export orientation and their tendency to dump goods in export market, if the duties are allowed to be exhausted, it would be tremendously disastrous for the Domestic Industry as well as these newly emerging manufacturers.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

15. The comments of the interested parties on the standing of the Domestic Industry are as below:
- i. The petitioning domestic industry has not come with clean hands before the Authority, and has obtained the initiation on misrepresentation of facts. It is stated that there are only 2 producers of the like article in India, whereas there are many other producers, having substantial capacities.
 - ii. The applicant has related parties in UAE, Indonesia and Thailand namely Saint Gobain Gyproc UAE, Saint Gobain Indonesia and Gyproc (Saint-Gobain) Thailand. The applicant wishes antidumping duty on imports from subject countries while having its own production in these countries. The applicant thus wants the best of both the worlds, while making producers in these countries suffer. Further, the applicant has excluded those products which are produced by its related entities in these countries so that the petitioner can import the same from these countries. It is not a question merely limited to eligibility or otherwise of the petitioner. It extends to the conduct of the petitioner, its will to restrict the supply sources selectively and at the same time reap the benefits of global production.

Examination by the Authority

16. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) ‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

17. The application in the present case has been filed by M/s Saint-Gobain India Private Limited. The production and share of the Indian producers during the period of investigation is as under:

Particulars	Jan 16- Dec 16 (POI)	
	M3	Share
M/s Saint Gobain India Pvt Ltd.	***	84%
M/s USG Boral Building Products (India) Pvt. Ltd.	***	16%
Total	***	100%

18. It may be noted from the above, the applicant accounts for around 84% of the total domestic production which may be considered as a major proportion of the domestic production of the subject goods.

19. The production of the petitioner alone constitutes around 84% of Indian production. Accordingly, the Authority holds that the petitioner satisfied the requirement of standing under Rule 5(3) and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

20. As regards the arguments of the interested parties that the petitioner has related parties in some of the subject countries, the Authority notes that the petitioner has submitted that it does not have any related party in any of the subject countries which is engaged in the production or trade of the subject goods.

21. As regards the contention of the interested parties that apart from the two producers mentioned by the Domestic Industry, there were other Indian producers during the period of investigation, the Authority notes that the Domestic Industry has submitted that owing to the nascent operation of the newly emerging producers, they were not in a position to acquire the information related to these producers at the time of initiation. In any case, the Authority notes that the applicant has enough share in total domestic production to be deemed as a Domestic Industry in terms of Anti-dumping Rules. The Authority further notes that, as submitted by the Domestic Industry, the emergence of the new Indian producers is a speaking proof that the current anti-dumping duties have been effective.

ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

Submissions by the Domestic Industries

22. The submissions made by domestic industry are as follows:

- i. The petitioner has claimed only such information as confidential, the confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
- ii. The petitioner has provided sufficient non confidential version of the application. No interested party has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the rules.
- iii. Information such as volume of exports to India, gross volume of sales in domestic market, production, sales, average price for exports to India have been provided in indexed version as the information is business proprietary information.
- iv. None of the exporters has provided the non-confidential version which is an exact replica of their confidential version. They have kept all the volume related information confidential. They have also not provided any statement of claim of confidentiality. Further, the responses are in stark violation of the specific guidelines issued by the Designated Authority with regard to the procedure to be followed for filing of non-confidential version of the exporter's questionnaire responses. We would, therefore, request the Hon'ble Designated Authority to disregard the submissions of the interested parties and also to reject the response of exporters and deny them the individual treatment.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

23. The various submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The petition suffers from excessive confidentiality. The petition provides absolutely no information with respect to volume related information also.
- ii. The domestic industry has claimed and has been allowed excessive confidentiality in the sense that they have not made available their annual report in the public file.
- iii. Domestic Industry has also not provided sufficient details of their costing.

Examination by the Authority

24. The Authority made available non confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).

25. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

“Confidential information”

- (1) *Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
- (2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
- (3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

26. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the information submitted by various interested parties in the form of public file.

NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**Normal Value**

27. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
- (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Submissions by the Domestic Industry

28. The submissions made by domestic industry are as follows:

- i. The Domestic Industry had filed full information with regard to the normal value and export price which was necessary for the purpose of initiation of an investigation. In terms of Rule 5, the Domestic Industry is required to give information which is sufficient to justify the initiation of an investigation. Necessary evidence had also been provided in support of their claim of normal value as well as export price.

- ii. China should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.

Views of the opposing interested parties

29. The normal value computed in the application for China PR is in contravention of the requirements as provided under Annexure I (7) of the AD Rules. Paragraph 10 of the Initiation Notification, as well as the Application, stipulates that the normal value for China PR be computed on the basis of the cost of production, duly adjusted.

Examination by the Authority

30. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers filed any response to the exporters questionnaire issued by the Authority.

31. Accordingly, the normal value and export price for the all the producers/exporters from the subject countries have been determined as below:

Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

32. The Authority has determined normal value having regard to para-7 of Annexure-I for the purpose of present investigation. The normal value for the subject products imported from China PR into India has been constructed considering optimum consumption norms of the domestic industry for major raw materials, cost of raw materials, is as per international prices, conversion cost, interest, SGA etc. at the levels allowed for the domestic industry. 5% of cost of sales excluding interest has been allowed towards reasonable profit.

Export price for producers and exporters in China PR

33. None of the exporters from China PR have provided any information giving details of export price. Therefore, the Authority has determined the export price for producers/exporters of China PR on the basis of the DGCI&S transaction wise data. Accordingly, the weighted average net export price at ex-factory level, in respect of all exporters from China PR has been determined after making due adjustments for Ocean Freight, Marine Insurance, Port Expenses, Bank charges, Commission and Inland freight on the basis of best available information as mentioned in the Dumping Margin table

Determination of Normal Value and Export price for M/s Gypsemna Co. (L.L.C.), Dubai and for other producers and exporters in UAE

34. M/s Gypsemna Co. (L.L.C.), Dubai: The questionnaire response filed by the exporter has been examined. The same is complete and in order. The cost of production was determined on the basis of verified information of the producer and domestic sale transactions were examined and found that the domestic sales are in the ordinary course of trade. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value based on complete domestic sales data. Producer has claimed adjustment on account of transportation, credit cost, insurance and the same have been accepted after necessary verification. The normal value is shown in the Dumping Margin Table below.

35. The Normal value for other producers in UAE has been correlated with the normal value arrived for M/s Gypsemna Co.

36. Export price for M/s Gypsemna Co. (L.L.C.), Dubai: During the POI, M/s Gypsemna Co. (L.L.C.), Dubai, has exported the subject goods to India directly. The exporter has claimed adjustment on account of inland transportation, overseas transportation, bank charges, credit cost and the same have been accepted after necessary verification. The net export price determined is shown in the Dumping Margin Table below.

37. The Authority has determined the export price for other non-responding exporters as per the facts available on record correlated with transaction-wise DGC&IS data.

Normal value and Export Price for producers and exporters from Indonesia and Thailand

38. The Authority notes that there were no exports of the subject goods from Indonesia and Thailand during POI. It is noted that the following exporters have submitted Questionnaire response and the same has been accepted by the Authority:

- a. M/s Siam Gypsum Industry (Songkhla) Co. Ltd.
- b. M/s Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co. Ltd.

- c. M/s PT Petrojaya Boral Plasterboard
- d. M/s PT. SIAM-INDO Gypsum Industry

DUMPING MARGIN

39. The dumping margin for subject goods has been determined by comparing constructed normal value and net export price. The table below shows the calculated dumping margin for producers/exporters from subject countries.

Sr. No	Country	Producer/Exporter	Normal Value (USD/M3)	Net Export Price (USD/M3)	Dumping Margin (USD/M3)	Dumping Margin %	Range %
1	China	All exporters/producers	***	***	***	***	100-110
2	UAE	M/s Gypsemna Co. (L.L.C.), Dubai	***	***	***	***	10-20
		Any Other Producer	***	***	***	***	55-65

METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**Views of the Domestic Industry**

40. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:

- i. Imports of the product under consideration have shown significant increase over the years with a significant increase in POI. Imports have also shown increase in relation to production and consumption in India;
- ii. Despite the anti-dumping duties in force, market share of subject countries in demand is increasing. Market share of the domestic industry has decreased in the POI as compared to the base year. The same is due to imports from subject countries;
- iii. With reduction in the prices by the foreign producers, the only choice available to the Indian producer is to either realign their prices with the changes in the import prices or to lose orders and hence the market share;
- iv. Domestic industry prices, reflects the effect of the prices that are being offered by the importers in the domestic market;
- v. The price underselling, price undercutting is positive and substantial. Further, the Domestic Industry is suffering from price depression as they are not able to increase its prices to reasonable terms. The main reason for this is high volume of imports from China that too at dumped and injurious prices.
- vi. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of profits, return on investments and cash profits to a very significant extent.
- vii. The decline in profitability of the domestic industry was due to significant increase in the import volume at non-remunerative prices from China.
- viii. The increase in selling price was lower than the increase in cost of production and thus the dumped imports are creating price suppression effect on the domestic industry.
- ix. The domestic industry has suffered material injury in connection with dumping of subject goods from China. Further, the domestic industry is threatened with continued injury, should the present condition continue.

Submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties

41. The following are the injury related submissions made by the opposing interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority

- i. The Domestic Industry is not suffering any injury and has improved throughout the injury investigation period;
- ii. There have been no imports from Indonesia and Thailand. Therefore, the question of any injury on account of imports from these two countries does not arise;

- iii. There is no price undercutting, price suppression and depression and therefore, the claim of Domestic Industry of any injury on account of imports from subject countries should be rejected;
- iv. The Domestic Industry has made huge improvements in terms of market share, profitability, ROCE etc. Therefore, it is established that there has been no injury to the Domestic Industry.
- v. The Domestic Industry has failed to establish any likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury.

Examination by the Authority

42. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Anti-Dumping Rules and considering the submissions made by the other interested parties.

43. As regards the submissions of absence of injury, the injury analysis carried out hereunder is self-explanatory to establish, if dumping has caused injury to the domestic industry or not.

44. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as below:

45. The AD Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

46. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of Anti-dumping rules states as under:-

(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

47. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration; while some may show improvement. The Designated Authority considers all injury parameters and thereafter concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments in the submissions.

Cumulative assessment

48. With regard to cumulative assessment Annexure II (iii) to the Rules provides as follows:

In cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the import of the like article or where the export of individual countries less than three percent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the imports of like article and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

49. The Authority notes that the imports are entering the Indian market simultaneously from the subject countries. Therefore, the issue of cumulative assessment of the injury caused to the domestic industry due to dumped imports from these sources has been examined with respect to parameters in Annexure II (iii) to the Rules. It was observed that:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	Jan 16 - Dec 16
Imports					
China PR	M3	367	5	287	1,014
Thailand	M3	586	123	0	0

UAE	M3	12,412	18,247	45,177	63,509
Indonesia	M3	0	0	0	0
Total Subject Countries	M3	13,365	18,375	45,464	64,524
Others	M3	125,387	164,062	204,499	216,712
Total Imports	M3	138,752	182,436	249,963	281,235

50. The table shows that there are no imports from Thailand and Indonesia during POI. Further, Indonesia has not exported any subject goods throughout the injury period.

51. In view of the above, the Authority holds that for the purpose of cumulative assessment, un-dumped imports from producers from subject countries have been taken out for the purpose of injury analysis.

Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

Import Volumes and Share of Subject country

52. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority has considered whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject good from the subject country has been analyzed as under:

Particulars	UoM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Import Volume					
Subject countries	M3	13365	18375	45464	64524
Other Countries	M3	125387	164062	204499	216712
Total Imports	M3	138752	182436	249963	281235
Domestic Industry	M3	446115	487013	554151	599914
Other Producers	M3	98815	105826	107317	111875
Indian Production	M3	544930	592839	661468	711789
Indian Consumption	M3	683682	775275	911431	993024
Imports from Subject Countries in relation to					
Total Production	%	2%	2%	5%	7%
Total Imports	%	10%	10%	18%	23%
Total Consumption	%	2%	2%	5%	7%

53. It is noted from the above table that imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute and relative terms in POI as compared to the previous years.

54. As seen from the Table at para 49 above, the overall imports from subject countries is primarily concentrated in UAE and China. Hence, the share of imports in relation to production and consumption primarily reflects the effect of imports from these two countries only. Thus, it is seen that the volumes from these two subject countries are significant in absolute terms as well as in relation to total imports.

Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

Price Undercutting

55. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

56. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The price of the domestic industry was

determined at the ex-factory level. The Authority has compared landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the subject goods.

Price Undercutting	UoM	China	UAE	Thailand	Indonesia	Subject countries
Import Volumes	M3	1014	63509	0	0	64524
Landed Value without AD Duty	Rs/ M3	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	0	0	100
Net Sales Realization	Rs/M3	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	0	0	100
Price Undercutting	Rs/M3	***	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	35-45	20-30	0	0	20-30
Landed Value with AD Duty	Rs/M3	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100			100
Net Sales Realization	Rs/M3	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100			100
Price Undercutting	Rs/M3	***	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	0-10	0-10	0	0	0-10

57. The above analysis shows that the Domestic Industry has suffered price undercutting from China and UAE at 1% and 6% respectively. Although, the Domestic Industry has claimed that they could not increase its selling price due to price pressure of low priced dumped imports from subject countries, the above table does not substantiate the same specially when examined/ correlated with the table at para 60 indicating a constant rise in domestic sales prices.

Price Underselling

58. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject countries. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports from each country. Comparison of the NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

Price Underselling	UoM	China	UAE	Thailand	Indonesia	Subject countries
Import Volumes	M3	1014	63509	0	0	64524
Landed Value without AD Duty	Rs/M3	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	0	0	100
NIP	Rs/M3	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	0	0	100
Price Underselling	Rs/M3	***	***	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***	***	***
Price Underselling	Range	20-30	0-10	0	0	0-10
Landed Value with AD Duty	Rs/M3	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100			100
NIP	Rs/M3	***	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	100			100
Price Underselling	Rs/M3	(***)	(***)	***	***	(***)
Price Underselling	%	(***)	(***)	***	***	(***)
Price Underselling	Range	(15) - (5)	(15) - (5)			(15) - (5)

59. It is noted from the above table that there is negative price underselling on account of imports of the subject goods from China and UAE. Further, there is no underselling from Indonesia and Thailand since there have been no imports from these two countries.

Price Suppression and Depression

60. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Price Suppression/Depression	UoM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Landed Value without ADD	Rs/M3	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	98	97
Landed Value with ADD	Rs/M3	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Cost of Sales	Rs/M3	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	92	90
Net Sales Realization	Rs/M3	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	103	102

61. From the above table, it is clear that the landed value of imports from the subject country have shown an upward trend in POI as compared to the previous years.

Economic Parameters of the Domestic Industry

62. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

63. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analyzed herein below.

Capacity, Production, and Capacity Utilization

64. The performance of the domestic industry with regard to production, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	UoM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Capacity	M3	605000	645000	663000	699000
Trend	Indexed	100	107	110	116
Production	M3	443740	484601	550016	587496
Trend	Indexed	100	109	124	132
Capacity utilization	%	73%	75%	83%	84%
Trend	Indexed	100	102	113	115

65. It can be seen that the production of the Domestic Industry has consistently increased throughout the injury period. The capacity utilization of the Domestic Industry also followed the same trend as that of production. It is noted that the installed capacity has also increased by 16% over the injury period.

Sales Volumes:

66. The sales parameters both in terms of volume and prices are demonstrated below:

Particulars		2013-14	2014-15	2015-16	POI
Domestic Sales Volume	M3	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	124	132
Domestic Sales Price	Rs. /M3	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	103	102
Total Sales Volume (including exports)	M3	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	124	132
Total Sales Price	Rs. /M3	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	103	102

67. It is noted that the sales volume of the Domestic Industry has increased gradually during the injury period with a substantial rise during the POI. The sales price has also been steady and increasing gradually in the injury period.

Market share:

68. The details of imports, domestic sales and the market share of the domestic industry is as below:

Particulars	UoM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Demand					
Subject countries imports	M3	13365	18375	45464	64524
Other Countries imports	M3	125387	164062	204499	216712
Domestic Industry Sales	M3	443740	484601	550016	587496
Other Producer Sales	M3	98815	105826	107317	111875
Total Demand	M3	681307	772864	907295	980606
Market Share in Demand					
Subject countries imports	%	2%	2%	5%	7%
Other Countries imports	%	18%	21%	23%	22%
Domestic Industry Sales	%	65%	63%	61%	60%
Other Producer Sale	%	15%	14%	12%	11%

69. As is clear from the above table, imports of the subject goods from subject countries have increased throughout the injury investigation period. The break-up of the subject countries exporting to India have been presented at the table at para 49 and may be seen from the table.

70. It is also noted that market share of domestic sales has decreased during POI as compared to the preceding years whereas market share of imports from subject country during the same period have increased, but not in the same proportion. Hence, the reason for decrease in the market share of Domestic Industry may be related to other countries imports, as evident from the table.

Profit/Loss, Cash Flow, Return on Capital Employed

71. The profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analysed as follows:

Particulars		2013-14	2014-15	2015-16	POI
Profit & Loss	Rs. /M3	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	495	582
Profit & Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	160	607	791
Depreciation	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	86	90
Cash Flow	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	228	280
Profit before Interest and Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	160	607	791
Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	88	85
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	199	692	930

72. The overall profitability parameters of the domestic industry has improved over the injury period.

73. It is noted that all figures in the table are self-explanatory with regard to quantum increase in profitability of the domestic industry. Further, the return on capital employed has shown significant increase throughout the injury period. In fact, its substantially high (almost nine times) in the POI when compared to the base year.

Inventories

74. The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table:

Particulars	Units	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Average Stock	M3	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	105	269
Production Per Day	No. of Days	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	124	132
Inventory as no. of production Days	No. of Days	5	7	5	11

75. It is noted from the above that the average stock of the Domestic Industry has been piling up of late.

76. The average no. of days for which the domestic industry was holding production in stock was calculated. It is found that the holding number of days production in stock is around 5 to 7 days during the injury period, increasing to 11 days in the POI. This cannot be considered as high.

Employment and Wages

77. The position with regard to employment and wages is as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
No. of Employees	No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	106	113
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	145	260	230
Wages per Employee	Rs/ No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	138	245	203

78. Authority notes that numbers of employees and the wages paid have increased from the base year till the period of investigation.

Productivity

79. It can be seen from the table below that productivity in terms of production per employee has increased by 17% in the POI as compared to the base year.

	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Production (MT)	M3	***	***	***	***
Employees	No.	***	***	***	***
Production/employee	MT/No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	117	117

80. The Authority notes that the figures relating to the productivity of the Domestic Industry has consistently improved throughout the injury period.

Growth

Growth	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Production year on year	%	-	9	13	7
Domestic Industry Sales year on year	%	-	9.3	13.0	6.9
Profit & Loss year on year	%	-	61	279	31
Market Share of Domestic Industry year on year	%	-	2.71	1.14	-0.51

81. The domestic industry has contended that with increase in demand, the domestic industry had expected growth in profits, comfortable cash flow and increase in return on investments. However, the domestic industry was not able to achieve the same to the desired levels due to the presence of the dumped imports from subject countries.

82. The analysis show that the Domestic industry sales year on year has increased with an exceptional rise in 2015-16.

Magnitude of Dumping:

83. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The analysis shows that the dumping margin determined against two of the subject countries is above *de minimis*.

Ability to raise Capital Investment:

84. There is no verifiable information presented by the Domestic Industry and neither available on records that can imply that future investment in the sector can be marred by the presence of dumped imports from subject countries, which in any case, account for 2% to 7% (range during the injury period) of the total production.

85. Ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector may not be affected due to the dumped imports from the subject countries.

Conclusion on Injury

86. Having regard to the information on record and after examination of the performance of the Domestic Industry, the Authority notes that the dumped imports of the subject goods from subject countries have increased in absolute terms. Marginal increase in imports is observed in relation to production and consumption of the subject goods in India.

87. The examination indicates that there is a healthy demand in India for the subject goods. It is also noted that the landed value of subject goods from subject countries are below the sales realization of the domestic industry. The domestic industry has been able to increase its prices in spite of the decrease in the cost of sales.

MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

88. The determined non-injurious price of the subject goods produced by the Domestic Industry has been compared with the landed value of the exports from subject countries for determination of injury margin during POI as under:-

Sr. No	Country	Producer/Exporter	NIP (USD/M3)	Landed Value (USD/M3)	Injury margin (USD/M3)	injury margin %	Range %
1	China PR	All exporters/producers	***	***	***	***	20-30%
2	UAE	M/s Gypsemna Co. (L.L.C.), Dubai	***	***	***	***	0-10%
		Any other producer	***	***	***	***	15-25%

LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**Views of the Domestic Industry**

89. The following are the submissions relating to the likelihood of dumping and injury made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:

- ii. The exporters in the subject countries have got huge production and surplus capacities of the subject goods. Further, the excess capacity available with such exporters is in itself many times the total production capacity of the Domestic Industry. The country wise production capacity and surplus capacity is as below:

Country	Capacity	Estimated exportable capacity	Capacity as % of capacity of Domestic Industry
UAE	1166250	816250	167%
Indonesia	1925000	500000	275%
China	22050000	6615000	3155%
Thailand	2600000	1575000	372%

- iii. The South African International Trade Administration recommended the continued imposition of anti-dumping duty on imports of gypsum plasterboard from Indonesia and Thailand.
- iv. The continued imposition of the duties by the South African Commission clearly establishes the fact the exporters from Indonesia and Thailand have indulged in dumping practices not only in India but also in other countries.
- v. The dumping practices of these countries along with the fact that these countries have huge exportable surplus further substantiate that in case the duties are not extended there is every possibility of continuation or recurrence of dumping and injury from the subject countries.
- vi. The existence of current dumping and injury margins in itself establish that the Domestic Industry is destined to suffer greatly if the current anti-dumping duties are revoked.

Submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties

90. The following are the submissions for examining likelihood of dumping and injury made by the opposing interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:

- i. The Domestic Industry has failed to prove that there is any likelihood of dumping or injury since all the parameters relating to the threat of material injury set out in in para (vii) Annexure II to the Anti-dumping Rules, 1995 are not met with in the present case.
- ii. Having mere capacity is not sufficient to prove likelihood of injury. The applicant is required to prove that the existence of such surplus capacity with the exporters would result in dumping of products in India. However, the

applicant failed to prove any such allegation and hence such an allegation doesn't stand the qualified evidence under the likelihood parameter.

- iii. While M/s Gypsemna cannot comment on the South African investigation against the PUC in the instant case, it is noteworthy to point out that no such duty was levied on imports from UAE. This goes to prove that even other jurisdictions have not found producers from UAE guilty of engaging in a practice of dumping goods.

Examination of Authority

91. The Authority has examined the contention of the Domestic Industry to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury with specific reference to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules. Clause (vii) of Annexure II to the rules read with Nirma Ltd. Vs Union of India 2017(346) E.L.T 328 (Guj) decided on 13/12/2016.

(a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation

92. As regards the argument regarding post POI data, it is noted that the Authority has not received post POI information from the exporters and other interested parties have not submitted their response as well.

93. Further the information pertaining to Post POI period, import data was not submitted by the domestic industry. Hence, the domestic industry has not established continuation of dumping of subject goods from subject countries post POI, with corroborating evidence. Further, the capacity detail given in the submission lacks the unit of measurement in which capacities of subject goods from subject countries have been estimated by domestic industry.

94. Further, the contention that domestic industry will continue to suffer injury because of continued dumped imports from subject countries, cannot be established in the instant case for the following reason: (a) In the present case, the domestic industry is not suffering injury on any of the economic parameters during the period of investigation, as seen from the preceding paragraphs on injury analysis and examination of major economic parameters (b) no verifiable documents submitted to claim injury in the post POI period.

b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports

95. This parameter for ascertaining the threat of material injury requires evaluation of existing surplus capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market. Domestic industry has claimed that the producers in subject countries are already faced with significant surplus capacities. Further, these producers are exporting the product to a large number of countries, a very significant proportion of which is being exported at a price below the prices in respect of India, thus showing likelihood of diversion of these exports to India in the event of withdrawal of Anti-Dumping duty. None of the interested parties have provided any verifiable evidence and information with regard to existing surplus capacities, and consequent likelihood /possibility of increased dumped exports to Indian market. Further, a communication was sent to the Domestic Industry to provide evidences of the same. No response has been received either.

(c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports

96. At the current landed price in India, there is price undercutting during POI without anti- dumping duty in case of the subject goods from only two of the subject countries viz. China and UAE.

(d) inventories of the article being investigated

97. The facts available on records do not contain any dependable evidence on inventories of the article being investigated.

(e) Price attractiveness of Indian market

98. The post POI transaction-wise import data of the import price, at which the subject goods are being exported by subject countries to India, is an indicator of the likelihood of continuation of dumping. No details of the same has been provided either by the Domestic industry or any other interested parties.

(f) Vulnerability of Domestic Industry in terms of price sensitivity of the product and the Indian market

99. It has been contended by domestic industry that the Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of such low priced imports from the subject countries in the market would cause an adverse impact on the

Domestic Industry. Given the facts of the instant case, and considering the above discussed current dumping and likelihood of dumping and injury parameters, it is noted that interested parties have not commented on the price sensitivity of the product that makes the domestic industry vulnerable.

OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK

100. Under Section 9A(5), the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports of the product under consideration during the review investigation period or not.
101. It was examined whether other parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It is noted as follows:

(a) Volume and prices of imports from third countries

102. The imports of the subject goods from countries other than the subject countries are significant as revealed by the transaction-wise data from DGC&IS. The pattern is seen throughout the injury period. The imports are reportedly higher in volume accounting for nearly 78% of the total imports during the period of investigation.

(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

103. There has been a steady increase in demand of the product concerned throughout the injury period.

(c) Developments in technology:

104. Technology for production of the product concerned has not undergone any change.

(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

105. There is no trade restrictive practice, which could have affected the Domestic Industry. The raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country.

(e) Export performance of the domestic industry

106. The injury analysis has been done by the Authority taking into consideration their domestic operations only. Therefore, performance in the export market has not affected the present injury analysis.

(f) Productivity of the Domestic Industry

107. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee as well as production per day has increased over the period.

POST DISCLOSURE STATEMENT

108. The issues raised at post disclosure stage have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions, whichever appropriate to the context and has factual basis have been summarized and again addressed as below. Further, issues have been addressed at respective paras in the present Final Finding:

Submissions made by the Domestic Industry

109. The comments submitted by domestic industry are summarized as below:
 - i. Sufficient time has not been given for submission of comments to the disclosure statement.
 - ii. Authority incorrectly analysed that there is no price pressure on the Domestic Industry.
 - iii. With the inclusion of Anti-Dumping Duty there is positive price undercutting from UAE and China.
 - iv. Serious price undercutting to the extent of 35% in case of China and 20-30% in case of UAE.
 - v. Disclosure statement didn't mention why price undercutting should not have been made on the basis of landed price without Anti-Dumping Duty.
 - vi. Failure to provide any comments as the Designated Authority hasn't provided the details of the NIP.
 - vii. Authority ignores serious positive and substantial price underselling in case of China and UAE.
 - viii. Current analysis of Designated Authority proves that the improved performance of Domestic Industry is only on account of Anti-Dumping Duty in place.
 - ix. Landed value with Anti-Dumping Duty reflected the same indexed numbers which is a typographical error
 - x. Issue a fresh disclosure statement with correct numbers as well as analysis on such corrected numbers.

- xi. Variation in capacity cannot be termed as an increase in capacity. Variation is mainly on basis of two major accounts a) due to reduction in weight of the product and b) increased the output by way of debottlenecking as reduction in product weight led to increase in line speed
- xii. Increase of 16% in capacity would imply increase of 48% in the POI when compared to the base year and which is not the case. Hence observation in the disclosure statement is incorrect and need new analysis.
- xiii. Volume of subject goods at dumped prices is increasing and therefore apart from current injury there is likelihood of future injury if the duties are revoked.
- xiv. Analysis failed to consider that all the imports during the POI are mainly from Oman, Saudi Arabia and Thailand.
- xv. Charts show that imports and market share from the subject countries have increased throughout the injury period in which landed value decreased.
- xvi. Market share of other countries in total imports also increased in same proportion as of increased in market share in imports from subject countries
- xvii. Observation in disclosure statement is flawed as far as analysis of landed value is taken in account
- xv. Analysis of the Authority in para 83 doesn't hold merit and is factually incorrect.
- xvi. Exporters refused to provide post POI data and are still being considered cooperating exporters.
- xvii. Incorrect to state that Domestic Industry has not established continuation of dumping as the post POI-import data has not been filed.
- xviii. Post POI data is limited to analysis of likelihood. Continuation of dumping itself gets established by the Authority
- xix. No request or direction was made by DGAD to Domestic Industry to provide post-POI data
- xx. Referring to para 44 the Domestic Industry noted that the Authority itself determined that the injury analysis carried out shows dumping caused injury to the Domestic Industry. Hence its beyond understanding how the Authority determined that the Domestic Industry is not suffering injury on any economic parameters.
- xxi. Post hearing the Domestic Industry made a request to DGAD to give authorization to obtain post-POI data and without waiting for the data the disclosure statement was issued.
- xxii. There is however no legal or logical requirement that the likelihood has to be carried out based on post POI data.
- xxiii. The unit of measurement for capacities has been estimated as M3 and mentioned in the application and the same should be noted by the Designated Authority.
- xxiv. Proper analysis of Exporter's Questionnaire Response would itself give an idea of existing surplus capacities with the producers.
- xxv. None of exporters or interested party has disputed the evidence provided by Domestic Industry in respect of surplus capacities from subject countries.
- xxvi. Referring to para 98 the Domestic Industry noted that Authority is incorrect as the Authority can determine the inventory related information from cooperating exporters from Part II of their responses.
- xxvii. Domestic Industry has come to know from market inputs that the landed price of subject goods from subject countries has further declined in post POI data.
- xxviii. Designated Authority ignored submission in regard to Anti-Dumping Duty imposed by other countries against the exports from subject countries.

Submissions made by the Exporters/producers and other interested parties

110. The comments submitted by other interested parties are as below:
- i. Exporter's Questionnaire Response was submitted with full evidence of cost of production and domestic and other prices, irrespective of the same, the Authority had ignored the response and concluded likelihood of recurrence of dumping because the same has been imposed by South African Authorities.
 - ii. Conclusion that can be drawn from the disclosure statement is that there is no current dumping or injury nor any likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury concerning imports of subject goods.
 - iii. Next Generation Standard board is also liable to be excluded for the sole reason that the same is not manufactured or imported into India. It also contains special properties.

- iv. Owing to petitioner's related parties in UAE, Thailand and Indonesia manufacturing the product under consideration, the petitioners are not eligible domestic industry under rule 2(b) of the Rules.
- v. From the conclusion noted by the Authority it can be concluded that there is no dumping from Thailand.
- vi. Agreement with the conclusion of the Authority that for the purpose of cumulative assessment, un-dumped imports should be taken out for the purpose of injury analysis.
- vii. Absence of dumped imports from Thailand concludes that there is no current dumping or injury from imports originating or exported from Thailand.
- viii. All the economic parameters as noted by Authority also indicate that Domestic Industry is not suffering injury and has been able to improve its position substantially.
- ix. In regard to the first factor of likelihood, there have been no imports from Thailand to India during the injury period and neither post POI. Thus, there is no indication of likelihood of any increased importation. Further, no depressing or suppressing effect on the prices of the Domestic Industry.
- x. In regard to freely disposable capacity; SGISB has a 100% capacity Utilization rate and doesn't have any freely disposable capacity. As far as SGISK is referred, there might have a minimal free capacity which is being utilized to cater the increasing demand in Thailand and other alternative markets. Hence no threat of any substantial increase in imports of the subject goods from Thailand and in future.
- xi. The South African Authority report cannot be relied upon owing to different POI in the investigation, determination was based on adverse facts and there were presence of exports from Thailand which is lacking in the current investigation.
- xii. The Authority did not terminate the investigation despite agreeing that there is no prima facie justification for continuation of the Anti-Dumping Duty.
- xiii. Accuracy and discrepancy existed in the petition as the application mostly contained self-serving and contradictory statements and the NCV version was insufficient and was inaccurate.
- xiv. Presence of related party in UAE should restrict the petitioner from claiming excessive capacities in UAE.
- xv. Authority is required to re-examine the issue of confidentiality
- xvi. Though the Authority has noted that the imports have increased in both absolute and relative terms the same should have been seen in the light of increase in demand, increase in sales of domestic industry and increased in imports from non-subject countries
- xvii. The Authority noted that the allegation that domestic industry couldn't increase the price because of low price imports is false. However, the same is due to the non-subject imports as can be established from comparable CIF import price of imports and higher landed price of imports from subject countries.
- xviii. The position taken by domestic industry in regard that the subject countries have affected the market share of Domestic Industry is untenable: market share held by Domestic Industry has remained stable (65-63% in first 2 years and 61-60% in last two years)
- xix. Imports from other countries increased sharply along with increase in demand
- xx. The Domestic Industry need to prove that the existence of surplus capacity would result in intensified dumping in India. Authority have noted of the same.
- xxi. Need for PCN wise analysis as the Product under consideration is being produced and sold in different types and thickness and the same has different cost and prices.
- xxii. Authority is requested to kindly note the comparable prices for the same type of board from subject and non-subject countries
- xxiii. Profitability, return on capital employed and cash profit of Domestic Industry improved significantly over the injury period.
- xxiv. The Domestic Industry has suffered injury in respect to imports from China
- xxv. UAE producers despite admitted capacities have not resorted to dumping in South African market, which shows absence of likelihood of increased imports in India in the event of cessation of antidumping duty at lower prices.
- xxvi. The producers in non-subject countries are also holding significant capacities and the current volumes of exports to India are quite insignificant having regard to their capacities.

- xxvii. If the foreign producers in non-subject countries are not finding Indian market as attractive, there is no reason why producers in subject countries would find Indian market attractive.

Examination by Authority

111. Most of the issues raised at post disclosure stage have been examined in above relevant paragraphs. Errors or omissions as pointed out in the disclosure statement have been rectified wherever necessary. The response of the Authority to the contentions raised post disclosure statement have been summarized below:
- i. Regarding availability of sufficient time for filing comments to disclosure statement, the Authority notes that sufficient time have been allowed to interested parties as per consistent practices of the Authority. It is also noted that most of the data/information in the disclosure statement pertains to the information provided by the petitioner domestic industry and therefore deemed to be within the knowledge of domestic industry. The domestic industry was merely called upon to consider such information, statements in the disclosure statement and offer its comments.
 - ii. The Authority does not agree that the submissions made by the petitioner with regard to injury or likelihood of injury have not been considered. All submissions made by the petitioner domestic industry have been adequately considered in the disclosure statement and Final Findings. However, where mere comments are reiterated without corroborating evidence, such comments have not been considered as essential facts. In fact, the domestic industry has advanced contradictory arguments with regard to injury. While contending that imports have caused injury to the domestic industry, the same has not been substantiated with facts and the same is also contrary to the facts on record with regard to performance of the domestic industry. The petitioner domestic industry has not shown any instance where the information/economic parameters adopted in the disclosure statement are materially different from what has been claimed by the petitioner. The authority has objectively examined various information provided by the petitioner and the same are in accordance with various legal provisions applicable in the instant case.
 - iii. The petitioner contended that price undercutting is positive after adding anti-dumping duty. It is noted that, the Authority has relied on the DGCIS data for the analysis apart from the submissions. The landed price of imports from subject countries after including ADD was materially higher than landed price of imports from non-subject countries. Further the volume import from non-subject countries was significantly higher than that from subject countries. This clearly shows that the petitioner could not have claimed that imports from subject countries have caused injury and imports from non-subject countries have not caused injury. Further, given the price and volume parameters of subject country imports vis-à-vis the non-subject country imports, the alleged price pressure on the domestic industry could not have been from imports from subject countries. It could have been due to imports from non-subject countries. The petitioner has provided no data/information/analysis to demonstrate that imports from non-subject countries did not create price pressure despite being at a lower price and being significantly higher in volumes.
 - iv. Regarding the contention regarding sales parameters of the domestic industry, the Authority notes that sales of the domestic industry increased over the injury period. Further, import from non-subject countries increased significantly over the injury period whereas import from subject countries in relation to production only increased by 5%. Thus, alleged decline in domestic sales could not be established because of dumped import from subject countries.
 - v. Regards alleged error in landed price of import, it is clarified that the indexed data has been presented correctly in the disclosure statement.
 - vi. The petitioner has contended that there was no increase in capacities and there was merely a variation in the capacities. However, the petitioner itself presented data wherein it has shown increase in capacity over the injury period. Whether such increase in capacity is due to addition of production facilities or de-bottlenecking or due to change in product mix or due to increased efficiencies is immaterial in deciding whether the capacities have increased over the period.
 - vii. The reference to post POI data is with regard to possible claim of likelihood by the interested parties based on post POI data. It is clarified that the Authority has not directed any party to provide post POI data. It is for the interested parties to decide whether they wish to rely upon post POI data to advance their case. Neither the domestic industry nor the exporters advanced the arguments in their favour based on post POI data and accordingly Authority has not examined merits of the case based on post POI data. While commenting on absence of post POI data from exporters, the domestic industry ignored that even domestic industry has not made any claims based on the basis of post POI data.
 - viii. Regarding the contention that the petitioner domestic industry, in fact had made efforts to collect post POI data and Authority did not provide adequate time, it is clarified that the Authority considers 6 months' period after the investigation period for post POI data submission as satisfactory. The post POI period in the instant case ended in June, 2017 and the Authority had held hearing in March, 2018. It was open for the interested parties to

obtain post POI data and advance their case on the basis of the same. The petitioner domestic industry however did not make efforts in collecting post POI data upto the stage of hearing and has now attempted to blame the Authority for not providing adequate time to the domestic industry while issuing disclosure statement. It is also noted that while domestic industry has advanced significant arguments with regard to post POI data, it has even contended that the post POI data is not even necessary for likelihood examination and the likelihood should be based on data for the present injury period. Thus, on one hand domestic industry sought rejection of data filed by exporters on the grounds that they have failed to provide post POI data whereas, on the other hand, the domestic industry questioned the need for post POI data. The contradictory statements given by the petitioner constraints the Authority to objectively examine the instant contention of the petitioner.

- ix. Regarding Para 44 of the disclosure statement, the Authority notes that the domestic industry has read this portion of the disclosure statement in isolation and not in totality. The averment at Para 44 of the disclosure statement is only with regard to the nature of examination carried out by the Authority and not with regard to conclusion by the Authority. This becomes all the more evident from the fact that the Para is placed at the beginning of the examination by Authority and even before analysis of various injury parameters. The Authority does not arrive at conclusions regarding existence of injury to the domestic industry without analysing injury parameters. Thus, the examination at Para 44 refers to only the nature of examination that has been carried out by the Authority and does not reflect a conclusion on injury by the Authority.
- x. The domestic industry contended that existence of positive price undercutting and injury margin itself implies whether domestic industry has suffered injury. The Authority however considers that there is no legal and factual basis for the same. The fact whether domestic industry has suffered injury is required to be determined having regard to the provisions of Annexure-II and mere existence of positive price undercutting, injury margin per-se does not imply that the domestic industry has suffered injury. In particular, the Authority considers whether performance of the domestic industry has deteriorated in order to hold that the domestic industry has suffered continued injury.
- xi. Contrary to the claim of domestic industry, the exporters have disputed the claim of domestic industry with regard to reliance on capacities as the sheer indicator of surplus capacities. The interested parties have contended that the domestic industry has equated capacities with surplus capacities.
- xii. The petitioner has argued that existence of current dumping is not necessary to consider likelihood or recurrence of dumping. The Authority however notes that in those situations where there is no current imports and hence current dumping, the petitioner is required to establish likelihood of recurrence of dumping of the product in the country. The petitioner has not been able to establish with corroborating evidence that there is likelihood of recurrence of dumping in the country. Further, the Authority notes that a communication was sent to petitioner on 21/3/2018 stating the following:

“Reference : Para 8 of the rejoinders which refers to the parameters to establish likelihood . Can you please list the evidences (references of documents that have been submitted) you have provided with regard to (1) huge surplus capacities (2) export orientation (3) dumping behavior (4) aggressive pricing strategies “

No response has been received from the petitioner on the same. The mail has been placed in the Public file.

- xiii. Regarding need for examination of causal link, the Authority clarifies that the Authority has consistently examined causal link even in sunset reviews. It is considered that the domestic industry is required to establish that cessation of ADD is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry. In a situation where domestic industry has not suffered continued injury, it is evident that there is no causal link between current dumping and injury to the domestic industry. Therefore, the Authority examined the likelihood of recurrence of injury due to likelihood of continued dumping in the event of cessation of anti-dumping duties.
- xiv. Regarding anti-dumping duty imposed by other countries against the exports from subject countries, the Authority notes that the antidumping duty has been imposed on those countries who have not exported the product in the Indian market. Whereas, those countries who are exporting the product in Indian market and suffering antidumping duty are not covered by these measures. Thus, the fact of imposition of antidumping duty by other countries does not establish likelihood of dumping and injury to the domestic industry.

CONCLUSION

112. Various statements in the petition showed that the petitioner itself admitted that it is not suffering injury. The petitioner contended that the Anti-dumping duty imposed played an effective role in development of domestic industry and providing necessary protection against imports. Further, volume of imports from subject countries declined significantly between original investigation POI to present POI.
113. The conclusion is summarized below:
 - i. Various economic parameters relating to Domestic Industry has shown improvement.

- ii. Domestic Industry failed to show that the injury has been suffered by Domestic Industry owing to imports.
- iii. Domestic Industry failed to substantiate their claim in relation to likelihood of injury to the domestic industry with cessation of Anti-Dumping duty.
- iv. The imports from non-subject countries are much higher in volume and comparable in price and are admittedly not causing injury wherein imports from non-subject countries and sales of Domestic Industry has increased more than imports from subject countries.

RECOMMENDATION

- 114. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal links. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal links in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority holds that there is no evidence that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in case the present Anti-Dumping duty is not extended further due to reasons given above, nor there is any causal link between the dumped imports and likely injury to the domestic industry. Therefore, the Authority does not recommend continuation of the anti-dumping duty on the imports of subject goods from the subject countries.
- 115. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority